आज का विचार

खूबसूरत रिश्तों को संभाल कर रखना साहब... अगर यह खो गए तो गूगल से भी नहीं ढूंढ पाओगे।

दैनिक सिटी दर्पण

आईना सच का

5

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ । वीरवार, 26 मार्च, 2026 | वर्ष 24, अंक 73, मूल्यः 3 रुपए, पृष्ठ 8 | RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 | www.citydarpan.com

पीएनजी और सीएनजी आपूर्ति पर जोर, भारत के पास ईंधन का पर्याप्त भंडार

मौजूद संकट को देखते हुए व्यावसायिक एलपीजी का आवंटन 50 फीसदी तक बढ़ा दिया गया

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच सरकार ने बुधवार को देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति स्थिति को सामान्य बताया है। भारत के पास ईंधन का पर्याप्त भंडार है। रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और लगभग 26 करोड़ टन तेल उपलब्ध है।

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 25 दिनों में 2.5 लाख नए पीएनजी कनेक्शन दिए गए, जबकि 2.2 लाख उपभोक्ता एलपीजी से पीएनजी पर चले गए और 2.5 लाख नए आवेदन प्राप्त हुए। शर्मा ने कहा कि एलपीजी की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। इसमें कोई कमी नहीं आई है, जबकि 92 फीसदी से ज्यादा बुकिंग ऑनलाइन हो रही है और बुकिंग का स्तर बढ़ने के बावजूद डिलीवरी सामान्य रूप से हो रही है। उन्होंने बताया कि व्यावसायिक एलपीजी का आवंटन 50 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें होटल, ढाबे, सामुदायिक रसोई और प्रवासी श्रमिकों जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत लगभग 22 हजार टन एलपीजी की आपूर्ति की गई है और 30 हजार छोटे सिलेंडर बांटे गए हैं। कई राज्यों में वैकल्पिक ईंधन के तौर पर अतिरिक्त केरोसिन (मिट्टी का तेल) का आवंटन भी किया गया है। उन्होंने

बताया कि इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली सीएनजी भी 100 फीसदी कंज्यूमर्स को उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि कई कंपनियों ने कई इंसेंटिव्स की घोषणा की है, जैसे 500 रुपये तक की फ्री गैस या सिक्योरिटी डिपॉजिट में छूट दी गई है।

सुजाता शर्मा ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसके तहत लगभग 2,700 जगहों पर छापे मारे गए हैं, जबकि 2,000 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों से अपील कर रही है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें और घबराएं नहीं। सरकार उन्हें पर्याप्त आपूर्ति का आश्वासन दे रही है। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकारों को भी लिखा गया है, उन्हें 10 फीसदी कमर्शियल गैस और अतिरिक्त एलपीजी देने का ऑफर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में ही एक ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें रोड रेस्टोरेशन चार्ज माफ कर दिया गया है और 247 पाइपलाइन के काम की इजाजत दी गई है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने बताया कि बुधवार को भारत सरकार ने पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक और गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इसका मुख्य मकसद सभी राज्यों में पीएनजी कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन फीस और अप्रूवल टाइमलाइन को आसान बनाना है।

सुजाता शर्मा ने कहा कि हमारे पास हर साल लगभग 26 करोड़ टन कच्चे तेल को रिफाइन करने की क्षमता है। पिछले दो दिनों में हमने कई इलाकों में रिटेल आउटलेट्स और पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लाइनें देखी हैं और लोग घबराकर भी खरीदारी करते दिखे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसी भी पेट्रोल पंप पर कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंपों को सप्लाई करने वाले टर्मिनलों पर भी पर्याप्त मात्रा में तेल मौजूद है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराकर खरीदारी करने से बचें।

पश्चिम एशिया संकट को लेकर सर्वदलीय बैठक, सरकार ने विपक्ष की शंकाओं को किया दूर

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया संकट को लेकर बुधवार को संसद भवन में हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विपक्ष की सभी शंकाओं को दूर कर उनके सभी सवालों का जवाब दिया। इस बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव का भारत पर प्रभाव और उससे निपटने के लिए सरकार के कदम के बारे में सभी दलों को अवगत कराया गया। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को छोड़कर सभी दलों के सदन के नेताओं ने भाग लिया। सर्वदलीय बैठक के बाद केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पत्रकारों को जानकारी दी कि सरकार ने विपक्ष के सभी सवालों और भ्रमों को स्पष्ट रूप से दूर कर दिया है। उन्होंने बताया कि सभी दलों से इस कठिन परिस्थितियों में सभी को एकजुट होकर काम करने बात कही, जिसे सभी दलों ने स्वीकारा। रिजिजू ने कहा कि गैस और पेट्रोलियम आपूर्ति, खासकर हर्मूज जलडमरूमध्य से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई, जिससे विपक्ष संतुष्ट नजर आया।

केंद्र योजनाओं की राशि का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करें अधिकारी: नायब सिंह सैनी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

भूपेंद्र शर्मा
चंडीगढ़

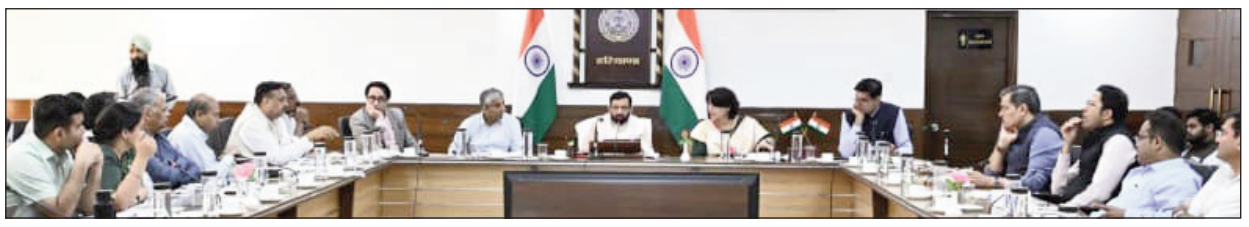

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदानों को लेकर विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं की समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त धनराशि के उपयोग, प्रगति एवं लंबित कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं में स्वीकृत बजट का समयबद्ध एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रदेश के नागरिकों को इन योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे अनुदानों का पूर्ण और पारदर्शी उपयोग राज्य के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विभागों को निर्देशित किया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत किए जाएं, ताकि आगामी किस्तों की स्वीकृति में कोई बाधा न आए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि जिन योजनाओं में प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है, उनमें तेजी लाई जाए और उनका त्वरित समाधान किया जाए। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी प्रशासनिक अधिकारी अपने-अपने विभागों में नोडल अधिकारी नामित करें जो निरंतर केंद्र सरकार के विभागों से समन्वय स्थापित करते रहें ताकि अनुदान राशि स्वीकृत और जारी होने में देरी न हो।

श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए तथा तकनीक के अधिकतम उपयोग के माध्यम से कार्यों की निगरानी की जाए। बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तायुक्त डॉ सुमिता मिश्रा, परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह, श्रम विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव रंजन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज अग्रवाल, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री विजय दहिया, वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री मोहम्मद शाइन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ अमित अग्रवाल, वित्त विभाग की आयुक्त एवं सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री शेखर विद्यार्थी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री अशोक मीणा, मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ राज नेहरू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

हरियाणा की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़कर भाग लेती हैं : सैनी

पंचकूला। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज 4 दिनों में 81 किलोमीटर कालका सिंहवाला तक की चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग पूरी करने वाली बेटियों से भेंट की। मुख्यमंत्री ने इस साहसिक उपलब्धि के लिए बेटियों की प्रशंसा की और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़कर भाग लेती हैं चाहे वह खेल का मैदान हो प्रशासनिक सेवाएं हों या फिर पर्यावरण संरक्षण की बात क्यों ना हो हरियाणा की बेटियां हर क्षेत्र में नाम रोशन करती हैं । हरियाणा सरकार भी युवाओं के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार बेहतर अनुभव और अवसर उपलब्ध कराने के लिए नई आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कर रही है। ताकि युवाओं को आगे बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण मिल सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा अपनी बहुमुखी प्रतिभा और रिकॉर्ड बनाने की परंपरा के लिए जाना जाता है । और आज बेटियों ने 4 दिनों में 81 किलोमीटर की ट्रैकिंग पूरी कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। सभी बेटियों को हार्दिक शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं । इस अवसर पर युवा कल्याण सेयोजक ने बताया कि यह कार्यक्रम हरियाणा सरकार के युवा कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि इस साहसिक कैंप में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की 6 छात्राओं डॉ शिवानी, डॉ वैशाली, डॉ रमन, डॉ अल्का, डॉ हिमानी, डॉ खुशबू, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय से काजल हिमांशी दीक्षा, सीनी ,वंशिका, मुन्नी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई, से अंतिम प्रिया तमन्ना अवी कोमल एमएसएम आयुर्वेद कॉलेज से सोनाली ने 81 किलोमिटर के चुनौतिपूर्ण और रोमांचकारी ट्रेकिंग कार्यक्रम में सम्मिलित होकर सफलतापूर्वक पूर्ण किया ।

भारत 6जी तकनीक में करेगा वैश्विक नेतृत्व: सिंधिया

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत 3जी के दौर में पीछे था, 4जी में विश्व के साथ चला, 5जी में आगे बढ़ा और अब 6जी में विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि देश अब 6जी तकनीक में वैश्विक नेतृत्व करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

सिंधिया ने बुधवार को लोकसभा में भाजपा सदस्य बिद्युत वरण महतो के एक सवाल पर कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में स्थापित भारत 6जी एलायंस का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। इससे जुड़े संस्थानों की संख्या 14 से बढ़कर 85 तक पहुंच चुकी है। भारत 6जी के क्षेत्र में विश्व के लगभग 10 प्रतिशत पेटेंट में योगदान करेगा, जिनमें से 4000 पेटेंट पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। भारत का सर्वव्यापी संपर्क प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय मंचों 3जीपीपी और आईटीयू में स्वीकृत हो चुका है।

उन्होंने कहा कि भारत 6जी एलायंस के अंतर्गत सात कार्य समूह सक्रिय हैं, जो स्पेक्ट्रम, उपकरण प्रौद्योगिकी, पुर्जे, हरित एवं स्थायित्व, जनसंपर्क और 6जी उपयोग मामलों जैसे क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं। इनकी प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है ताकि समयबद्ध और प्रभावी विकास सुनिश्चित हो सके।

सिंधिया ने अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) के बारे में बताया कि इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में फरवरी 2024 में बनाया गया। इसका उद्देश्य देश में अनुसंधान और नवाचार को नई गति देना है। वर्ष 2023 से 2028 की अवधि के लिए 50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें वित्त मंत्री द्वारा 14,000 करोड़ रुपये का बजट घोषित किया गया है।

उन्होंने कहा कि एएनआरएफ के तहत आठ प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें उन्नत अनुसंधान अनुदान, प्रधानमंत्री प्रारंभिक करियर अनुसंधान अनुदान, समावेशिता अनुसंधान अनुदान, उत्कृष्टता केंद्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र, नवाचार संकेतक और विश्लेषण, तीव्र नवाचार एवं अनुसंधान साझेदारी और एएनआरएफ अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र शामिल हैं। इसके अलावा उत्कृष्टता केंद्रों, नवाचार केंद्रों, अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग और फैलोशिप कार्यक्रमों के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत न केवल 6जी तकनीक में वैश्विक नेतृत्व स्थापित करेगा बल्कि अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में भी नई मिसाल कायम करेगा।

ट्रेनों में 78 प्रतिशत सीटें सामान्य और स्लीपर वर्ग की : वैष्णव

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेल में लगभग 78 प्रतिशत सीटें सामान्य और गैर-एसी स्लीपर वर्ग की हैं, जिससे आम और मध्यम वर्ग के यात्रियों को बड़ी राहत मिल रही है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे की कुल लगभग 69 लाख सीटों में से करीब 54 लाख सीटें गैर-एसी (सामान्य और स्लीपर) वर्ग की हैं, जबकि लगभग 22 प्रतिशत (15 लाख) सीटें एसी श्रेणी में हैं।

रेल मंत्री ने कहा कि ट्रेनों के डिब्बों की संरचना में भी आम यात्रियों को प्राथमिकता दी गई है। वर्तमान में लगभग 70 प्रतिशत डिब्बे गैर-एसी (सामान्य और स्लीपर) हैं, जिनकी संख्या करीब 62 हजार है, जबकि एसी डिब्बों की संख्या लगभग 27 हजार है। उन्होंने बताया कि यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेल ने पिछले पांच वर्षों (2021-22 से फरवरी 2026 तक) में 1024 नई ट्रेनें शुरू की हैं, 907 ट्रेनों का विस्तार किया है, 168 ट्रेनों के फेरे बढ़ाए हैं और 4651 अतिरिक्त डिब्बे जोड़े हैं।

मंत्री ने कहा कि कम आय और मध्यम वर्ग के यात्रियों को सस्ती यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 17,000 गैर-एसी डिब्बों के निर्माण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2022-23 में 553 करोड़ यात्रियों के मुकाबले 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 651 करोड़ हो गई है, जो इस वर्ग की बढ़ती मांग को दशार्ता है। भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे द्वारा त्योहारों और अवकाश के दौरान विशेष ट्रेनों का संचालन भी बढ़ाया गया है। वर्ष 2025-26 (फरवरी तक) में लगभग 74,800 विशेष ट्रेन यात्राएं संचालित की गईं। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की संरचना में सामान्य और स्लीपर वर्ग के डिब्बों की संख्या अधिक रखी जा रही है, ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को सस्ती और सुलभ यात्रा का लाभ मिल सके। उन्होंने भरोसा जताया कि भविष्य में भी यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए इसी तरह के कदम उठाए जाते रहेंगे।

उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर रांची को प्रशासन ने किया नो फ्लाइंग जोन घोषित

एजेंसी (हि.स.)
रांची

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के 28 मार्च को रांची आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके मद्देनजर बिरसा मुण्डा एयरपोर्ट से हिनू चौक से बिरसा चौक-अरगोड़ा चौक से लोकभवन एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रांची के 200 मीटर की परिधि को ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून के संदर्भ में अनुमंडल दंडाधिकारी सदर की ओर से नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। यह निषेधाज्ञा 28 मार्च के प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे के लिए लागू रहेगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर की ओर से बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की गई है। 28 मार्च को बिरसा मुण्डा एयरपोर्ट से हिनू चौक से बिरसा चौक से अरगोड़ा चौक से लोकभवन एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रांची के 200 मीटर की परिधि को ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून के संदर्भ में नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है तथा उक्त क्षेत्र में तथा उसके ऊपर ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून पूर्णतः वर्जित रहेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस

प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। दौरे की तैयारियों को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है। मुख्य सचिव स्तर से लेकर जिला स्तर तक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं, ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की कोई चूक न हो। इसी क्रम में 25 मार्च को मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। वहीं 26 मार्च को राजभवन से एयरपोर्ट तक के रूट पर काफिले की रिहर्सल भी की जाएगी, ताकि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सभी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है।

मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना: जौनपुर के 29 प्रगतिशील किसानों को कृषि उपकरण मिले

एजेंसी (हि.स.)
देवरिया

मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में नवीन सब्जी मंडी स्थित समिति भवन में बुधवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में देवरिया सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने पात्र लाभार्थी 29 प्रगतिशील किसानों को विभिन्न कृषि उपकरण वितरित किए। उन्होंने किसानों को ट्रैक्टर, रोटावेटर, एलईडी टीवी समेत कई उपयोगी कृषि उपकरण प्रदान किए, जिससे उनकी खेती को आधुनिक और अधिक लाभकारी बनाने में मदद मिलेगी। योजना का उद्देश्य किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त कर उनकी आय में वृद्धि करना है। वही मुस्लिम वर्ग के प्रगतिशील किसान खुर्शीद आलम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ट्रैक्टर प्रदान किया गया, जिससे उनके

चेहरे पर खुशी साफ झलकती नजर आई।

मुख्य अतिथि डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किसानों के उत्थान और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाएं सीधे किसानों तक पहुंच रही हैं, जिससे उनकी आय बढ़ाने और खेती को आधुनिक बनाने में सहायता मिल रही है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों- चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से जुड़े हों, के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसी भावना के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

कार्यक्रम में लाभार्थी किसानों ने सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की योजनाएं उनके लिए काफी लाभकारी साबित हो रही हैं।

कार्यक्रम के दौरान मंडी समिति के सचिव दिवाकर उपाध्याय, समाजसेवी इस्राफील उर्फ गब्बर, भाजपा के मनोनीत सभासद बजरंगी मणि सहित बड़ी संख्या में किसान, स्थानीय जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने श्रीराम नवमी पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम नवमी के मंगलमय अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हृदय से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में बुधवार को उन्होंने कहा कि मयार्दा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम का दिव्य जीवन सत्य, धर्म, त्याग, मयार्दा और करुणा सहित समस्त मानवीय मूल्यों का सर्वोच्च प्रतीक है। प्रभु श्रीराम का चरित्र न केवल व्यक्तिगत आचरण को दिशा देता है, बल्कि समाज और शासन-व्यवस्था को भी न्याय, समरसता और उत्तरदायित्व की राह पर अग्रसर करता है। मुख्यमंत्री योगी कहा कि श्रीराम का आदर्श हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, संयम और कर्तव्यनिष्ठा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और यही मूल्य ह्यरामराज्यह्न की संकल्पना का आधार है। उन्होंने कहा कि श्रीराम नवमी का यह पावन पर्व हमें अपनी सनातन मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ते हुए लोकमंगल, सेवा और परोपकार के भाव को आत्मसात करने का संदेश देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे इस पावन अवसर पर प्रभु श्रीराम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें तथा समाज में सद्भाव, सौहार्द और परस्पर सहयोग की भावना को सुदृढ़ करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जनपदों के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि श्रीराम नवमी के पर्व को शान्तिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए समुचित और प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया कि प्रदेश के समस्त श्रीराम मन्दिरों, पूजा स्थलों एवं धार्मिक परिसरों में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जाए, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन-पूजन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। साथ ही, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, भीड़ प्रबन्धन के प्रभावी उपाय तथा सतत निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी प्रकार की असुविधा या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे इस उत्सव को पूरी श्रद्धा, उल्लास एवं अनुशासन के साथ मनाएं, सामाजिक सौहार्द बनाए रखें तथा प्रदेश की गरिमा और परम्परा के अनुरूप इस पर्व को एक आदर्श उत्सव के रूप में मनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रभु श्रीराम की कृपा से प्रदेश में सुख, शान्ति, समृद्धि एवं खुशहाली का वातावरण और अधिक सुदृढ़ होगा तथा उत्तर प्रदेश निरन्तर विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा।

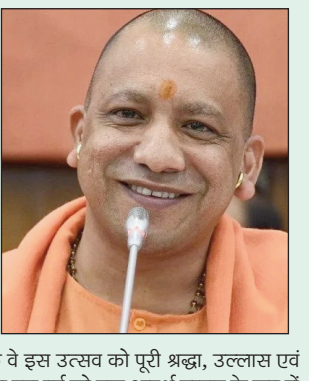

हिमाचल की टैक्सियों और एलएमवी पर टोल टैक्स नहीं लगेगा सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए पास पर होगा विचार: सुक्खू

कहा, सरकार को वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 54 करोड़ रुपये अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि प्रदेश की टैक्सियों और एलएमवी (हल्के मोटर वाहनों) पर कोई टोल टैक्स नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने यह जानकारी विधायक राकेश जम्वाल, सुखराम चौधरी और राकेश कालिया के संयुक्त सवाल के जवाब में दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोग, जिन्हें रोजाना काम या अन्य कारणों से राज्य की सीमाओं से होकर आना-जाना पड़ता है, उनके लिए पास जारी करने के मुद्दे पर कैबिनेट में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो बाहरी लोग नियमित रूप से हिमाचल में आते-जाते हैं, यदि वे अपने वाहन हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत करवाते हैं तो उन्हें टोल से संबंधित राहत मिल सकती है। उन्होंने बताया कि जहां राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और राज्य सरकार के टोल बैरियर साथ-साथ स्थित हैं, उन्हें एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य के टोल बैरियर को फास्टैग प्रणाली से जोड़ दिया है और टोल टैक्स में उतनी वृद्धि नहीं की गई है, जितनी चर्चा हो रही है। इस दौरान अनुपूरक सवाल के माध्यम से विधायक राकेश कालिया और सुखराम चौधरी ने कहा कि सीमा से सटे गांवों के लोग व्यापार और उद्योगों में काम करने के लिए रोजाना आवाजाही करते हैं, इसलिए उन्हें पास की सुविधा दी जानी चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस सुझाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी से सरकार को वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 54 करोड़ रुपये अधिक राजस्व मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि प्रवेश शुल्क में वृद्धि से सरकार को कुल मिलाकर लगभग 228 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रवेश शुल्क बढ़ाने से पर्यटन उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अभी आकलन नहीं किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस फैसले से प्रदेश में महंगाई बढ़ने या आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की संभावना बहुत कम है।

अटल आदर्श विद्यालय बंद नहीं किए, सरकार अधूरे काम कर रही पूरे : मुख्यमंत्री

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने अटल आदर्श विद्यालयों को बंद नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्व सरकार के समय शुरू किया गया था और जो काम अधूरा रह गया था, उसे वर्तमान सरकार पूरा कर रही है। उन्होंने यह जानकारी विधायक अनुराधा राणा के सवाल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अनुपूरक सवाल के जवाब में दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों का पूरा सम्मान करती है। उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रदेश में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अटल आदर्श विद्यालय आवासीय स्कूल हैं, जबकि राजीव गांधी के नाम से बनाए जा रहे स्कूलों में डे बोर्डिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे विद्यार्थियों को दिन के समय पढ़ाई और अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे पहले मूल सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि जिला लाहौल-स्पीति में तीन राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से ऐसे स्कूलों की स्थापना कर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है।

पीएम श्री स्कूल कोटली टांडा में भव्य स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन, 81 विद्यालयों को खेल किट वितरित

एजेंसी (हि.स.)
जम्मू

पीएम श्री गवर्नमेंट हाई स्कूल, कोटली टांडा में वार्षिक स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों में खेल भावना और समग्र शिक्षा का उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में अखनूर के विधायक मोहन लाल भगत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि मुख्य शिक्षा अधिकारी अजीत शर्मा विशिष्ट अतिथि और उपमुख्यशिक्षा अधिकारी प्रदीपसिंह रकवाल विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके अलावा जोनल शिक्षा अधिकारी अखनूर हरजीत सिंह, सभी क्लस्टर प्रमुख, हाई स्कूल कोटली टांडा के प्रधानाचार्य नसीब सिंह रकवाल तथा जोन अखनूर के सभी हाई, मिडिल और प्राइमरी स्कूलों के प्रमुख भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरूआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन से हुई। प्रधानाचार्य नसीब सिंह ने स्वागत भाषण देते हुए विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें शैक्षणिक और सह-शैक्षणिक गतिविधियों में विद्यालय की उपलब्धियों को रेखांकित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए जिन्होंने सभी का मन मोह लिया। साथ ही वॉलीबॉल मैच का भी आयोजन किया गया जिसमें खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर का मुख्य आकर्षण समग्र शिक्षा अभियान के तहत 81 विद्यालयों को खेल किट का वितरण रहा। इनमें 53 प्राथमिक विद्यालय, 24 मिडिल स्कूल और 4 पीएम श्री विद्यालय शामिल हैं। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और शारीरिक फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाना है। मुख्य शिक्षा अधिकारी अजीत शर्मा ने विद्यालय द्वारा बनाए गए उच्च मानकों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के मानदंड अन्य सरकारी स्कूलों में भी लागू किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत है और खेलकूद तथा अन्य गतिविधियों को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए। मुख्य अतिथि विधायक मोहन लाल भगत ने विद्यालय की उत्कृष्ट व्यवस्था, स्वच्छता और आधारभूत सुविधाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे, डस्टबिन, सोक पिट और सुसज्जित किंडरगार्टन कक्षाएं उपलब्ध हैं, जो इसे निजी स्कूलों के समकक्ष खड़ा करती हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता और कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है।

बिलासपुर-मनाली-लेह रेल लाइन बनेगी हिमाचल के लिए गेमचेंजर : सांसद हर्ष महाजन

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

हिमाचल प्रदेश में रेलवे विकास को लेकर लंबे समय से चली आ रही मांग अब तेजी से साकार होती नजर आ रही है। आजाद भारत में पहली बार राज्य को बड़े स्तर पर रेल परियोजनाओं की सौगात मिलने पर सांसद हर्ष महाजन ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है।

सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि राज्यसभा में रेल मंत्री द्वारा दी गई जानकारी से स्पष्ट है कि हिमाचल में रेल विस्तार कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने विशेष रूप से चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन और भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेल लाइन पर तेज गति से चल रहे कार्यों को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बिलासपुर-मनाली-लेह रेल लाइन परियोजना हिमाचल के लिए गेमचेंजर साबित होगी। लगभग 489 किलोमीटर लंबी इस सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रेल लाइन का सर्वेक्षण पूरा कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यह रेल लाइन सुंदरनगर, मंडी, मनाली, सिस्सू, दारचा, केलांग, सरचू और उपशी होते हुए लेह तक जाएगी। इससे मंडी जिले की कनेक्टिविटी को विशेष मजबूती मिलेगी और यह क्षेत्र पर्यटन व व्यापार का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। बॉक्स रेल परियोजनाओं को मिली रफ्तार जानकारी के अनुसार चंडीगढ़-बद्दी नई रेल लाइन परियोजना पर लगभग 1540 करोड़ रुपये की लागत अनुमानित है, जिसमें केंद्र और हिमाचल सरकार की 50:50 साझेदारी तय की गई है। फरवरी 2026 तक इस परियोजना पर 1068 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं।

पुलिस ने बारामूला में ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया प्रतिबंधित पदार्थ बरामद

जम्मू। नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ अपने निरंतर अभियान को जारी रखते हुए बारामूला में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया। पुलिस स्टेशन कुंजर की एक पुलिस पार्टी ने चिचिलोरा कुंजर में नियमित गश्त के दौरान एक संदिग्ध वाहन (एचआर 55 एडी 2930) को रोका। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति मौके से भाग गया, जबकि चालक वहीद सुल्तान पुत्र मोहम्मद सुल्तान गनी निवासी शीरपोरा बंगिल, पट्टन को पकड़ लिया गया। उसकी तलाशी के दौरान 27 ग्राम चरस बरामद हुई। उसके खुलासे पर मजिस्ट्रेट और संबंधित नंबरदार द्वारा प्रतिनियुक्त राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में एसएचओ पीएस कुंजर की देखरेख में फरार आरोपी जियाकत अहमद डार पुत्र मोहम्मद रमजान डार निवासी चिचिलोरा, कुंजर के आवास पर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान करीब 1 किलो 690 ग्राम चरस पाउडर बरामद हुआ। इस संबंध में, एफआईआर संख्या 35/2026 यू/एस 8/20-29 एनडीपीएस अधिनियम के तहत पीएस कुंजर में मामला दर्ज किया गया है। जांच जारी है और फरार आरोपियों को पकड़ने के प्रयास भी जारी हैं।

नवरात्रि के बीच माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी, 2.4 लाख श्रद्धालुओं ने किये दर्शन

एजेंसी (हि.स.)
कटरा

श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर में बुधवार को भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि चल रहे चैत्र नवरात्रि उत्सव में देश भर से भक्तों की लगातार भीड़ उमड़ रही है। नवरात्रि के शुरूआती दिनों में 2.4 लाख श्रद्धालु पहले ही दर्शन कर चुके हैं और कटरा से भवन तक मार्ग पर तीर्थयात्रियों की आवाजाही लगातार बनी हुई है।

अधिकारियों ने बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एहतियात के तौर पर पंजीकरण प्रक्रिया को निलंबित कर दिया था। स्थिति में सुधार और बेहतर भीड़ प्रबंधन के साथ पंजीकरण अब बहाल कर दिया गया है। श्री माता वैष्णो देवी की सुरक्षित और परेशानी मुक्त तीर्थयात्रा की सुविधा के लिए सुरक्षा कर्मियों, चिकित्सा टीमों और सहायक कर्मचारियों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित की गई है। श्रद्धालुओं को उचित पंजीकरण के बाद ही यात्रा करने और प्रशासन के सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है।

श्री माता वैष्णो देवी जी के पवित्र मंदिर की तीर्थयात्रा के लिए पंजीकरण 21 मार्च की पूर्व संध्या पर भक्तों की भारी आमद के कारण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन 22 मार्च को सुबह 4 बजे फिर से शुरू हो गया। चूंकि नवरात्रि तीर्थयात्रा के लिए एक शुभ अवधि है, इसलिए आने वाले दिनों में तीर्थयात्रियों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। यात्रा पूरे जोरों पर है और त्रिकुटा पहाड़ियां 'जय माता दी' के जयकारों से गूंजती रहती हैं। नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति भक्तों के बीच मजबूत आस्था को दर्शाती है। चल रहे चैत्र नवरात्रि उत्सव के मद्देनजर श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है, इसलिए देश भर से हजारों भक्त माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं।

संक्षिप्त-समाचार

बसोहली में सड़क सुरक्षा के लिए जीडीसी का वाकाथॉन, युवाओं ने दिया जागरूकता का संदेश

कठुआ/बसोहली। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बसोहली के सड़क सुरक्षा क्लब द्वारा सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक जागरूकता ह्यवाकाथॉनह्ल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर समाज को जिम्मेदार यातायात व्यवहार का संदेश दिया। वाकाथॉन कॉलेज परिसर से शुरू होकर बसोहली के पलाही क्षेत्र से गुजरा जहां प्रतिभागियों ने हाथों में जागरूकता संबंधी प्लेकार्ड लेकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति सचेत किया। इस दौरान सीट बेल्ट और हेलमेट के अनिवार्य उपयोग, ट्रैफिक संकेतों के पालन, अपनी लेन में चलने और निर्धारित गति सीमा का पालन करने जैसे महत्वपूर्ण नियमों पर जोर दिया गया। प्रतिभागियों ने नारे लगाकर और राहगीरों से संवाद कर शराब पीकर वाहन चलाने के खतरों के प्रति भी जागरूक किया तथा सभी वाहन चालकों से जिम्मेदारीपूर्वक व्यवहार करने की अपील की। कार्यक्रम ने आम जनता का ध्यान आकर्षित करते हुए सामुदायिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया। यह आयोजन कॉलेज की प्राचार्या प्रो. राज किरण शर्मा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, जिनके नेतृत्व ने कार्यक्रम की सफलता में अहम भूमिका निभाई। ह्यसड़क सुरक्षा क्लबह्ल के सदस्यों के समर्पित प्रयासों और प्रभावी समन्वय से कार्यक्रम को व्यापक जनसहभागिता मिली। कॉलेज की यह पहल सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दशार्ती है और सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर युवाओं व स्थानीय समुदाय को जागरूक करने में संस्थान की सक्रिय भूमिका को उजागर करती है।

जम्मू-कश्मीर के विश्वविद्यालयों में लगभग 40 फीसदी शिक्षकों के पद खाली

जम्मू। जम्मू-कश्मीर में लगभग एक दर्जन विश्वविद्यालय संकाय की भारी कमी से जूझ रहे हैं और लगभग 40 प्रतिशत शिक्षण पद खाली पड़े हैं। उच्च शिक्षा विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यरत नौ सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और दो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 3,300 से अधिक शिक्षण पद स्वीकृत हैं, जबकि केवल 1,900 ही पद पर शिक्षक हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि जम्मू विश्वविद्यालय में 442 स्वीकृत पदों के मुकाबले 252 शिक्षक हैं। कश्मीर विश्वविद्यालय में 570 स्वीकृत पदों के मुकाबले 373 शिक्षक हैं, यानी लगभग 35 प्रतिशत की कमी है। जम्मू के कृषि विश्वविद्यालयों में 411 स्वीकृत पदों के मुकाबले 237 शिक्षक हैं, जबकि कश्मीर के कृषि विश्वविद्यालयों में 540 स्वीकृत पदों के मुकाबले 424 शिक्षक हैं और लगभग 21 प्रतिशत पद खाली हैं। अन्य संस्थानों में राजौरी के बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय में 241 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 93 शिक्षक हैं, यानी जिससे 60 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 385 स्वीकृत पदों के मुकाबले 135 शिक्षक हैं और लगभग दो-तिहाई पद खाली हैं। कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में 195 स्वीकृत पदों के मुकाबले 108 शिक्षक हैं, जबकि जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में 177 स्वीकृत पदों के मुकाबले 160 शिक्षक हैं। इसी प्रकार, क्लस्टर विश्वविद्यालय जम्मू और श्रीनगर में क्रमश 16 और 56 स्वीकृत पदों के मुकाबले 13 और 18 शिक्षक हैं।

नेशनल हाइवे की दुर्दशा से परेशान मंडी के लोग, पार्षद ने उपायुक्त को बताए हालात

मंडी। बाघा बार्डर अटारी लेह नेशनल हाइवे 003 जो मंडी शहर से गुजरता की दुर्दशा ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। पिछले तीन सालों से इस मार्ग का एक हिस्सा जो मंडी शहर के नगर निगम वार्ड 6 सनयारड़ी व 5 रामनगर से होकर गुजरता है, केहनवाल मार्ग के कैंची मोड़ से केहनवाल चौक होकर पुलघराट तक जाता है की हालत ऐसी है कि इस पर वाहन चलाना तो दूर पैदल चलना भी खतरे से खाली नहीं। लोगों सालों से चीख चिल्ला रहे हैं मगर मोर्थ यानी भूतल परिवहन विभाग के अधिकारियों के कान में जूं नहीं रेंग रही। रामनगर के पार्षद योग राज योगा ने उपायुक्त मंडी को दिए पत्र में कहा कि कैहनवाल कैंची मोड़ से लेकर मंगवाई पुलघराट की सड़क जो राष्ट्रीय राजमार्ग 003 के अधीन आती है की स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी है। इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस बारे में कई बार विभाग व प्रशासन को लिखा गया व लिखित एवं मौखिक तौर पर भी बताया गया मगर कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि इस बारे में सतर्कता विभाग को भी शिकायत भेजी गई क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन सड़कों के लिए बजट की आमतौर पर कोई कमी नहीं होती फिर भी इस कई सालों से मरम्मत नहीं किया गया। 2023 व 2025 की प्रलयकारी बारिश ने इसे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। जनता ने दबाव बनाया और मामला सतर्कता विभाग के पास गया तो कुछ महीने पहले इस पर मिट्टी डाल कर लीपापोती की गई जो अब धूल का कारण बन रही है। उन्होंने कहा कि यह मार्ग मंडी शहर के प्रवेश द्वार है।

हिमाचल में तीन नए सैटेलाइट शहर विकसित करने के लिए एमओयू

शिमला। हिमाचल प्रदेश में नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। प्रदेश में तीन नए सैटेलाइट शहर विकसित करने के लिए हिमाचल प्रदेश हाउसिंग व शहरी प्राधिकरण (हिमुडा) और हाउसिंग एंड अर्बन डिवेल्पमेंट कॉपोर्रेशन लिमिटेड (हुडको) के बीच बुधवार को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी भी मौजूद रहे। इस समझौते के तहत प्रदेश में 'हिम चंडीगढ़', 'हिम पंचकुला' और 'कांगड़ा वैली एयरोसिटी' नाम से तीन नए सैटेलाइट शहर विकसित किए जाएंगे।

दैनिक सिटी दर्पण आईना सच का
न्योन्मेषक: स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापक: स्व. सतपॉल शर्मा
स्वामी, प्रकाशक मुद्रक एवं संपादक भूपिंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1, सेक्टर 40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित-160036
सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।
स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्क: 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में कुलपति ने किया 'हुनर हाट' का शुभारंभ

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर द्वारा महिला किसानों को सशक्त बनाने एवं ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए विश्वविद्यालय परिसर के गेट संख्या-3 पर 'हुनर हाट' विपणन एवं विक्रय केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस केंद्र का उद्घाटन कुलपति डॉ. ए.के. पांडा द्वारा किया गया, जो महिला समूहों एवं कृषि आधारित स्टार्टअप्स को सतत बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस मौके पर कुलपति ने कहा कि इस प्रकार की पहलें ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने तथा कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि विश्वविद्यालय नवाचार, मूल्य संवर्धन तथा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे किसानों की आय एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि हो सके।

'हुनर हाट' केंद्र महिला किसान हित समूहों, स्वयं सहायता समूहों, तकनीकी लाइसेंसधारकों तथा स्टार्टअप्स द्वारा विकसित उत्पादों के विपणन हेतु एक समर्पित मंच के रूप में कार्य करेगा। यह पहल 'कृषि में महिलाएं' विषयक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना तथा हिम पालम आरकेवीवाई-रफ्तार कार्यक्रम के अंतर्गत पोषित स्टार्टअप्स के सहयोग से संचालित की जा रही है।

इस केंद्र में जैविक एवं मूल्य संवर्धित उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है, जिसमें मौसमी अचार एवं संरक्षित खाद्य पदार्थ, पौष्टिक आटा एवं ताजे बेकरी उत्पादों के साथ-साथ हस्तनिर्मित वस्तुएं जैसे सिलाई किए हुए बैग एवं पारंपरिक हस्तशिल्प शामिल हैं।

डॉ राजीव बिंदल ने मेडिकल कॉलेज नाहन को लेकर सरकार को घेरा

नाहन। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में नाहन स्थित डॉ. वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज को शहर से बाहर स्थानांतरित करने की सिफारिशों को मंजूरी दिए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने बुधवार को सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार 2022 में सत्ता में आई थी और यदि मेडिकल कॉलेज को शिफ्ट करना ही था तो शुरूआत में निर्णय लिया जाना चाहिए था। अब साढ़े तीन साल बाद लिया गया यह फैसला क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय है, क्योंकि नए संस्थान को बनने में कम से कम पांच वर्ष लगेंगे। इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर नकारात्मक असर पड़ेगा। बिंदल ने यह भी आरोप लगाया कि नाहन में प्रस्तावित नर्सिंग कॉलेज और माता-शिशु अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी अधूरे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से इसके लिए धनराशि भी उपलब्ध करवाई गई थी, लेकिन राज्य सरकार इन योजनाओं को धरातल पर उतारने में विफल रही है। उनके अनुसार, कांग्रेस सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा एंट्री टैक्स को 70 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये करने के निर्णय की भी कड़ी आलोचना की।

नाहन-कुमारहट्टी हाईवे पर दो हादसे पेट्रोल से भरा टैंकर पलटा, बोलेरो भी दुर्घटनाग्रस्त

एजेंसी (हि.स.)
नाहन

नाहन-कुमारहट्टी नेशनल हाईवे 907ए पर पच्छाद क्षेत्र में बुधवार को 2 अलग-अलग सड़क हादसे पेश आए हैं। पहले हादसे में पेट्रोल से भरा एक टैंकर हाईवे किनारे पलट गया। वहीं, अन्य हादसे में एक बोलेरो वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों दुर्घटनाएं मंगलवार देर शाम सामने आईं। सराहां पुलिस ने दोनों हादसों की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार पेट्रोल से भरा एक टैंकर सराहां की तरफ से किन्नौर जा रहा था। जैसे ही टैंकर चरानी घाट के समीप पहुंचा तो अचानक सड़क किनारे पलट गया। गनीमत ये रही कि हादसे के दौरान अति ज्वलनशील पदार्थ से भरे टैंकर ने आग नहीं पकड़ी। हालांकि, चालक ने बेकाबू हुए टैंकर को काबू करने के भरपूर प्रयास किए, लेकिन मोड़ गहरा होने के कारण चालक का वाहन से संतुलन बिगड़ गया। बड़ी बात ये है कि इस हादसे में चालक की जान बच गई। वहीं, एक अन्य हादसे में चरावग के समीप एक बोलेरो जीप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। पुलिस के अनुसार हादसे के वक्त वाहन में एक महिला सहित तीन लोग सवार थे। इस दुर्घटना में महिला को काफी चोटें आई हैं, जबकि दो अन्य लोगों को मामूली चोटें लगीं। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने राहत व बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सराहां पुलिस ने इस दुर्घटना का केस दर्ज कर लिया है। साथ ही हादसे की जांच शुरू कर दी है।

फेडरेशन कप में कांस्य पदक जीतकर हिमाचल कबड्डी टीम ने रचा इतिहास

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

मध्य प्रदेश के सतना में आयोजित पांचवी कबड्डी फेडरेशन कप में हिमाचल को कबड्डी टीम ने कांस्य पदक जीता है। जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष टेक चंद शर्मा ने बताया कि भारत के मध्य प्रदेश में कबड्डी फेडरेशन कप आयोजित किया गया, जिसमें देश की आठ टॉप टीमों ने भाग लिया। यह कप महिला, पुरुष वर्ग खेला गया। हिमाचल ने पहली मर्तबा महिला व पुरुष कबड्डी टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। सेमीफाइनल मुकाबला सर्विस के साथ हुआ। दुर्भाग्य से इस सेमीफाइनल मुकाबले में हिमाचल टीम के कप्तान शिवांश ठाकुर जो जिला मंडी से ताल्लुक रखते हैं घायल हो गए जिस वजह से यह मुकाबला हिमाचल के हाथ से निकल गया।

उन्होंने बताया कि लड़कियों की टीम ने भी दमखम दिखाया तथा उन्होंने भी कांस्य पदक हासिल किया। हिमाचल कबड्डी टीम में मंडी से शिवांश ठाकुर, रजत चौधरी और लड़कियों में भावना ठाकुर ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से मांग की है की हिमाचल कबड्डी टीम के कप्तान शिवांश ठाकुर और अन्य खिलाड़ियों को पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर नियुक्ति दी जाए। उन्होंने कहा कि कबड्डी खेल को और बेहतर बनाने के लिए हिमाचल कबड्डी संघ काम कर रहा है तथा ग्रामीण परिवेश से और बेहतर खिलाड़ी निकले जाएंगे जो देश और प्रदेश के लिए मेडल लेकर आएंगे। प्रदेश के लिए कांस्य पदक लेकर आए कबड्डी टीम के प्रत्येक सदस्य का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत किया जाएगा।

मौसम | **हिमाचल में कई स्थानों पर आसमानी बिजली गिरने की आशंका**

28-30 के लिए आंधी-बिजली और ओलावृष्टि का येलो-ओरेंज अलर्ट

- मौसम विभाग के अनुसार 26, 27 और 31 मार्च को भी प्रदेश में मौसम खराब रहेगा

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम के तेवर तीखे होने वाले हैं। मौसम विभाग ने 28 से 30 मार्च के बीच राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी, गरज-चमक, ओलावृष्टि और बारिश की संभावना जताते हुए येलो और ओरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन तीन दिनों के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और कई स्थानों पर आसमानी बिजली गिरने की भी आशंका है।

मौसम विभाग का कहना है कि 29 मार्च को राज्य के अधिकांश हिस्सों में ओलावृष्टि की संभावना ज्यादा है, इसलिए इस दिन के लिए ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 28 और 30 मार्च को तेज हवाओं और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट रहेगा। इन दिनों में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, खासकर किसानों, यात्रियों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विभाग के अनुसार 26, 27 और 31 मार्च को भी प्रदेश में मौसम खराब रहेगा, हालांकि इन दिनों के लिए किसी प्रकार की औपचारिक चेतावनी जारी नहीं की गई है। विभाग ने बताया कि उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाले दो वेस्टर्न डिस्टरबेंस 26 मार्च से सक्रिय होंगे और दूसरा 28 मार्च की रात से असर दिखाएगा। इनके प्रभाव से प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। बीते कुछ दिनों से मार्च महीने में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण प्रदेश में दिसंबर जैसी ठंड महसूस की जा रही है। लोग एक बार फिर गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार बदलों की आवाजाही और वर्षा के कारण आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड का असर फिर बढ़ेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई। धर्मशाला में 5.1 मिलीमीटर, मंडी में 2.8 मिलीमीटर, जोगिंदरनगर में 7.0 मिलीमीटर, बागी में 2.3 मिलीमीटर, सुंदरनगर और बरठीं में 0.2-0.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कांगड़ा क्षेत्र में गर्जना और बिजली गिरने की घटना भी दर्ज हुई। हालांकि बुधवार को शिमला सहित अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के कुकुमसेरी और ताबो में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे रिकॉर्ड किया गया।

हरियाणा में नशे के खिलाफ अभियान तेज- 31 मार्च तक जिला-स्तरीय कार्ययोजना

गिरफ्तारियों में 16 प्रतिशत और अंतर्राज्यीय कार्रवाई में 37 फीसदी बढ़ोतरी, मुख्य सचिव ने की राज्य स्तरीय एनसीओआरडी बैठक की अध्यक्षता

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने नशीले पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए अपने अभियान को और तेज करते हुए एक समन्वित एवं तकनीक आधारित रणनीति अपनाने का निर्णय लिया है।

आज यहां मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई 12वीं राज्य स्तरीय नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) बैठक में राज्य की प्रगति की समीक्षा की गई और भविष्य की कार्य-योजना तय की गई।

बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, पुलिस महानिदेशक श्री अजय सिंघल तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में प्रवर्तन कार्रवाई में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान दर्ज एफआईआर की संख्या 3,330 से बढ़कर 3,738 हो गई, जो 12.25 प्रतिशत की वृद्धि है। इसी प्रकार गिरफ्तारियां 6,095 से बढ़कर 7,053 हो गईं, जो 15.72 प्रतिशत की वृद्धि दशार्ती हैं। मध्यम मात्रा से जुड़े मामलों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई और इनकी संख्या 1,985 से बढ़कर 2,610 हो गई, जो 31.49 प्रतिशत की वृद्धि है। व्यावसायिक मात्रा के मामलों में अंतर्राज्यीय गिरफ्तारियां 444 से बढ़कर 610 हो गईं, जो 37.39 प्रतिशत वृद्धि को दशार्ती हैं।

इस दौरान निवारक कार्रवाई को भी बल मिला है। निरोधात्मक कार्रवाई की संख्या 12 से बढ़कर 76 हो गई, जो पांच गुना से अधिक वृद्धि है। मादक पदार्थ नेटवर्क के वित्तीय स्त्रोतों पर भी प्रभावी कार्रवाई करते हुए वर्ष 2025 में 144 आरोपियों की संपत्तियां कुर्क की गईं, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 54 थी। कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य 7.55 करोड़ रुपये से बढ़कर 13.59 करोड़ रुपये हो गया, जो लगभग 80 प्रतिशत वृद्धि है।

बैठक के दौरान संदिग्ध नशे के कारण होने वाली मौतों के मामलों की भी समीक्षा की गई। प्रभावित जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, वरिष्ठ

औषधि नियंत्रण अधिकारियों तथा जिला समाज कल्याण अधिकारियों को नशा पीड़ितों के उपचार एवं पुनर्वास के लिए प्रतिक्रिया प्रणाली को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने पिछली बैठक की कार्यवाही की समीक्षा करते हुए नियामक उपायों का सख्ती से पालन के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित प्रहरी क्लबों को सक्रिय भूमिका निभाने और नशा तस्करों की सूचना साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सर्वाधिक सटीक सूचना देने वाले क्लबों को स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया जाएगा।

बैठक के दौरान बताया गया कि दोहरे उपयोग (ड्यूल-यूज). वाली दवाओं की बिक्री करने वाली केमिस्ट शॉप्स में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। नियमों का पालन न करने पर लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। सिरसा जिले में पिछले तीन महीनों में 1,737 मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया गया, जिनमें लगभग 18 प्रतिशत में सीसीटीवी खराब पाए गए और लगभग 27 प्रतिशत दुकानों में पंजीकृत फार्मासिस्ट न मिलने पर सुधारात्मक कार्रवाई की गई। बैठक में यह भी बताया गया कि नशे से जुड़ी गतिविधियों में बार-बार संलिप्त पाए गए 63 नशा अपराधियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद की गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन को प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की निगरानी के लिए विशेष सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए कहा गया है। साथ ही, सभी नशामुक्ति केंद्रों का निरीक्षण निर्धारित मानकों के अनुसार किया जा रहा है।

जनवरी 2026 में हुई शीर्ष स्तर की एनसीओआरडी बैठक के निदेर्शों के अनुरूप, हरियाणा नेटवर्क आधारित प्रवर्तन, वित्तीय ट्रेल की अनिवार्य जांच तथा परिणाम आधारित निगरानी प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जिला स्तर पर कार्य-योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिन्हें 31 मार्च, 2026 तक लागू किया जाएगा। इसके अलावा, एनडीपीएस अधिनियम के तहत समयबद्ध अभियोजन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अगले महीने एक ही दिन सभी जिलों में जिला-स्तरीय बैठकें आयोजित की जाएं और उनकी समेकित रिपोर्ट अगली राज्य स्तरीय एनसीओआरडी बैठक में प्रस्तुत की जाए, ताकि जिलावार प्रदर्शन का व्यापक आकलन किया जा सके।

बैठक में संस्थागत सुदृढ़ीकरण के तहत हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय मधुबन (करनाल) से पंचकूला स्थानांतरित करने के एक प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। इसके अलावा, पंचकूला में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए समर्पित थाना स्थापित करने की भी योजना है। फॉरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए जीसी-एमएस, जीसी-एफआईडी और यूवी-एचपीएलसी जैसी उन्नत मशीनें स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही प्रेगाबालिन, सिग्नेचर कैप्सूल और टैपेंटाडोल जैसी दवाओं को एनडीपीएस ढांचे में लाने का सुझाव भी दिया गया। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को सख्त निगरानी, समयबद्ध क्रियान्वयन और ठोस परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए नशामुक्त हरियाणा के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

बैठक में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी. अनुपमा, उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अपूर्व कुमार सिंह, हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एडीजीपी श्री संजय कुमार और ब्यूरो के एसपी श्री मोहित हांडा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

विकसित भारत-जी राम जी से संबंधित प्रतियोगिताओं की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

- प्रतियोगिताओं में लोगो डिजाइन, राष्ट्रीय रील/वीडियो चैलेंज एवं ऑनलाइन क्विज होगी शामिल

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ह्लविकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) – वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) अधिनियम, 2025 के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इन प्रतियोगिताओं में लोगो डिजाइन, राष्ट्रीय रील/वीडियो चैलेंज एवं ऑनलाइन क्विज शामिल हैं जिसकी अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है। प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वीबी-जी राम जी अधिनियम के बारे में व्यापक, प्रचार– प्रसार व जागरूकता के लिए अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहा है। इन प्रतियोगिताओं में युवा, विद्यार्थी व आम नागरिक भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि मायगव पोर्टल पर आयोजित लोगो डिजाइन प्रतियोगिता तथा माय भारत पोर्टल पर आयोजित राष्ट्रीय रील/वीडियो चैलेंज 60 सेकेंड्स फॉर माय विलेज एवं विकसित भारत-जी राम जी क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभागी भाग ले सकते हैं और अपनी प्रवृष्टियां भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में प्रविष्टि जमा करने की अंतिम तिथि 04 अप्रैल 2026 कर दी गई है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय रील/वीडियो चैलेंज की अंतिम तिथि 05 अप्रैल 2026 कर दी गई है, जबकि विकसित भारत-जी राम जी क्विज प्रतियोगिता की अंतिम तिथि 07 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि यह पहल युवाओं को अपने गांवों के विकास से जोड़ते हुए ह्युवा शक्ति७-पंचायत प्रगति की भावना को सशक्त बनाएगी।

आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों पर एनीमिया जांच और आयरन सप्लीमेंटेशन के लिए करेंगे समन्वय स्थापित

सिटी दर्पण संवाददाता
लाडवा

एसडीएम लाडवा अनुभव मेहता ने कहा कि एचपीवी टीकाकरण के लाभ को देखते हुए इसको ज्यादा से ज्यादा अमल में लाने के लिए जागरूकता फैलाएं। एचपीवी के लिए बाजार में प्राइवेट प्रैक्टिशनर के द्वारा यह टीकाकरण 2500 रुपए में किया जा रहा है, जबकि सरकारी संस्था में यह बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों पर एनीमिया जांच और आयरन सप्लीमेंटेशन को नियमित करने के लिए समन्वय स्थापित करेंगे।

एसडीएम अनुभव मेहता एनीमिया मुक्त हरियाणा अभियान और एचपीवी वैक्सीन को लेकर आयोजित महत्वपूर्ण समन्वय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, फूड सप्लाई विभाग व कमेटी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार की एनीमिया मुक्त हरियाणा पहल को और प्रभावी बनाना तथा किशोरियों में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान को तेज गति से लागू करना था। उन्होंने कहा कि एचपीवी वैक्सीनेशन के लिए लक्षित किशोरियों की सूची तैयार करना और अभिभावकों को जागरूक करने के लिए शिविरों का आयोजन के लिए शिक्षा विभाग से तालमेल कर अग्रिम कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की।

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. कृष्ण कांत ने कहा कि एनीमिया मुक्त हरियाणा अभियान के तहत बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम के लिए नियमित जांच, आयरन की गोलियां, पौष्टिक आहार और जागरूकता कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने सभी विभागों को अनुरोध किया कि लक्षित समूहों तक पहुंच सुनिश्चित की जाए और अभियान को मिशन मोड में चलाया जाए।

एचपीवी वैक्सीनेशन के संबंध में डॉ. सोनिया व डॉ. वनिता ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा 14 वर्ष की आयु वाली किशोरियों (जिन्होंने 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की) को मुफ्त एचपीवी वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। यह वैक्सीन गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव में अत्यंत प्रभावी है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा लाडवा से राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ 28 फरवरी 2026 पर किए जाने के बाद जिले में भी इस दिशा में तेजी से कार्यवाही की जा रही है।

बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी नीलम सैनी, संजय गांधी मेमोरियल पब्लिक स्कूल लाडवा राजबीर शर्मा, पूनम शर्मा, बाल विकास परियोजना अधिकारी लाडवा उषा कंबोज, विनय गांधी, डॉ. विनीत, डॉ. सोनिया व जसमेर कुमार स्वास्थ्य निरीक्षक विशेष रूप से उपस्थित रहे।

संक्षिप्त-समाचार

आम चुनाव और उपचुनाव 2026: भारत निर्वाचन आयोग ने अंतर-राज्यीय सीमा बैठकें आयोजित कीं

चंडीगढ़। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने चुनाव वाले 5 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और उनके 12 सीमावर्ती राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के साथ तैयारियों की समीक्षा करने, समन्वय बढ़ाने के लिए समीक्षा बैठक की और सभी संबंधित अधिकारियों को हिंसा-मुक्त, धमकी-मुक्त और प्रलोभन-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त डॉ. एस.एस. संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मिलकर असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में आगामी आम चुनाव और 6 राज्यों में उपचुनाव के लिए चुनाव तैयारियों, कानून व्यवस्था की स्थिति, अवैध नकदी, शराब, नशीले पदार्थों, हथियारों की जब्ती, अंतरराज्यीय चेक पोस्ट और व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों की समीक्षा की। मतदान वाले राज्यों ने आयोग को अपनी समग्र तैयारियों, कानून व्यवस्था संबंधी मुद्दों, व्यय प्रवर्तन और केंद्रीय एजेंसियों तथा पड़ोसी राज्यों के साथ लंबित मुद्दों के बारे में जानकारी दी। सीमावर्ती जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया और मतदान वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीमाओं को सील कर दिया गया। पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों को निर्देश दिया गया कि वे मतदान करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रलोभन मुक्त और हिंसा मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने में सहायता के लिए हर संभव कदम उठाएं। आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि एजेंसियों अर्थात सीबीडीटी, सीबीआईसी, ईडी, डीआरआई, सीईआईबी, एफआईयू-आईएनडी, आरबीआई, आईबीए, एनसीबी, आईसीजी, बीसीएएस, एएआई, डाक सेवा, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आरपीएफ, आईटीबीपी, भारतीय तटरक्षक बल और असम राइफल्स के प्रमुखों को मतदान वाले राज्यों और इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से सटे क्षेत्रों में कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने और अंतरराज्यीय चेक पोस्टों पर जांच बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

मेटाबोलिक रोग अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉ. दुर्बा पाल को मिलेगा राजीब गोयल पुरस्कार

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा 3 अप्रैल 2026 कोआयोजित होने वाले प्रतिष्ठित राजीब गोयल पुरस्कार समारोह में मेटाबोलिक रोगों, सूजन (इन्फ्लेमेशन) और मधुमेह से संबंधित अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉ. दुर्बा पाल को सम्मानित किया जाएगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलगुरु एवं गोयल अवार्ड आयोजन समिति के चेयरमैन प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने बताया कि 45 वर्ष से कम आयु के चार प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को राजीब गोयल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक पुरस्कार के अंतर्गत विजेताओं को पदक, प्रशस्ति-पत्र तथा एक लाख रुपये की नकद राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि 3 अप्रैल 2026 को विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में आयोजित इस भव्य समारोह में देश-विदेश के अनेक प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी, जिससे यह आयोजन युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा। आयोजन समिति के सह-अध्यक्ष प्रो. एस.पी. सिंह ने बताया कि डॉ. दुर्बा पाल का जन्म 15 जून 1982 को पंजाब के पटियाला में हुआ। उन्होंने वर्ष 2002 में बी.एससी. तथा 2004 में जूलॉजी में एम.एससी. की डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने विश्वभारती विश्वविद्यालय से शोध कार्य करते हुए वर्ष 2015 में पीएच.डी. की उपाधि अर्जित की।

होनहार छात्रों की मदद के लिए पूर्व छात्रों ने शुरू की छात्रवृत्ति योजना

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) कुरुक्षेत्र (पहले रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, कुरुक्षेत्र) में होनहार छात्रों की मदद के लिए पूर्व छात्रों द्वारा फंडेड एक स्कॉलरशिप - आर ई सी के -66 पूर्व छात्र छात्रवृत्तिह्न शुरू की गई है। आर ई सी के के 1966 बैच के पूर्व छात्रों ने ठक्ळ कुरुक्षेत्र के एलुमनाई सेल के जरिए 40 लाख का फंड देकर योग्य छात्रों के लिए ≈एलुमनाई स्कॉलरशिप≈ शुरू करने में उदारता से योगदान दिया है। डीन (छात्र कल्याण), प्रो. प्रतिभा अग्रवाल ने कहा कि यह स्कॉलरशिप हर साल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के चार मेधावी, प्रथम वर्ष के इ.ळ्ीूँ छात्रों को दी जाएगी। इस पहल के तहत चुने गए प्रत्येक छात्र को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रो. अग्रवाल ने आगे बताया कि इस योजना को निरंतरता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और यह चार वर्षों तक जारी रहेगी, जिससे कई

बैचों के योग्य छात्रों को लगातार सहायता मिलना सुनिश्चित होगा। बी टैक के छात्रों को ₹20,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की पहल न केवल आर्थिक राहत प्रदान करती है, बल्कि शैक्षणिक उत्कृष्टता और समावेशिता को भी बढ़ावा देती है। इस योजना का मकसद पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन को पहचान देना है, साथ ही होनहार छात्रों को उनके इंजीनियरिंग के सफर की शुरूआत में ही आर्थिक मदद देना है। संस्थान के डायरेक्टर ने कहा कि यह योगदान पूर्व छात्रों और उनके पुराने संस्थान के बीच मजबूत रिश्ते को दिखाता है, और साथ ही इंजीनियरों की आने वाली पीढ़ियों को संवारने के प्रति उनके समर्पण को भी दिखाता है। यह पहल एन आई टी, कुरुक्षेत्र में पूर्व छात्रों द्वारा किए जा रहे योगदानों की बढ़ती लिस्ट में एक और कड़ी है, जो समाज को कुछ वापस देने और छात्रों की सफलता में मदद करने की संस्कृति को और मजबूत करती है।

सेवा वितरण में सुधार हेतु हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन-त्रिपुरा सरकार के बीच समझौता

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन और त्रिपुरा सरकार के बीच ऑटो अपील सिस्टम के अपनाने और उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है।

आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि इस समझौते का उद्देश्य सेवा वितरण में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित करना है। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन द्वारा विकसित ऑटो अपील सिस्टम (अअर) एक तकनीक-आधारित प्रणाली है, जो अपीलों के स्वतः एस्केलेशन के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सहायक है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय द्वारा भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की गई है, ताकि सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके। इसी क्रम में त्रिपुरा सरकार ने इस प्रणाली को अपनाने में रुचि दिखाई है।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि समझौते के अनुसार, अअर का स्वामित्व पूर्ण रूप से हरियाणा राइट टू सर्विस आयोग के पास रहेगा और त्रिपुरा सरकार को इसका सीमित, गैर-विशिष्ट और गैर-हस्तांतरणीय उपयोग का अधिकार दिया गया है। यह प्रणाली केवल सरकारी और सार्वजनिक सेवा वितरण के उद्देश्यों के लिए ही उपयोग की जाएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रणाली का किसी भी प्रकार का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकेगा और बिना पूर्व अनुमति के किसी तीसरे पक्ष के साथ इसे साझा नहीं किया जाएगा। त्रिपुरा सरकार द्वारा प्रणाली के उपयोग के दौरान हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन को स्त्रोत के रूप में उचित श्रेय देना अनिवार्य होगा।

प्रवक्ता ने बताया कि यह प्रणाली सहयोगात्मक संघवाद की भावना के तहत त्रिपुरा सरकार को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, आवश्यकतानुसार हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन तकनीकी मार्गदर्शन और परामर्श भी प्रदान करेगा, हालांकि इसके कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी वित्तीय या परिचालन जिम्मेदारी का वहन आयोग द्वारा नहीं किया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि दोनों पक्ष इस समझौते के तहत साझा की गई तकनीकी और प्रशासनिक जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेंगे। यह समझौता पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा, जिसे आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी भी विवाद की स्थिति में समाधान आपसी परामर्श से किया जाएगा तथा आवश्यक होने पर मामला चंडीगढ़/पंचकूला के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आएगा।

फिल्म फेस्टिवल छात्रों के सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास का परिचायक: प्रो. सोमनाथ सचदेवा

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग द्वारा संस्कृति सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चरल डेवलपमेंट, कुरुक्षेत्र के सहयोग से 8वें हरियाणा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भव्य शुभारंभ गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, कुवि कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा सहित उपस्थित अतिथियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर सभी अतिथियों द्वारा वियतनाम में नवंबर माह में आयोजित होने वाले ओवरसीज फिल्म फेस्टिवल तथा इंडो-मोरक्को ओवरसीज फिल्म फेस्टिवल के पोस्टरों का भी विमोचन किया गया।

अपने आशीर्वचन में स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि भारतीय सिनेमा हमारी समृद्ध संस्कृति और मूल्यों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म महोत्सव विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिसके माध्यम से वे सिनेमा के जरिए संस्कृति और समाज को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। उन्होंने महोत्सव की टैगलाइन ह्लसिनेमा से सरोकार, संस्कृति से प्यारह्व की सराहना की।

मुख्य अतिथि कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि फिल्म फेस्टिवल छात्रों के सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास का परिचायक है। सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज, संस्कृति और विचारों को जोड़ने का सशक्त मंच भी है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में इस प्रकार के आयोजन विद्यार्थियों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उन्होंने इस सफल आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे फिल्म महोत्सव विद्यार्थियों में रचनात्मकता, संवेदनशीलता और सांस्कृतिक समझ को विकसित करते हैं।

विशिष्ट अतिथि हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ललित बतरा ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के फिल्म महोत्सव सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के साथ-साथ विभिन्न देशों की परंपराओं और विचारों को समझने का अवसर प्रदान करते हैं।

वहीं डॉ. बिस्वरूप रॉय चौधरी ने कहा कि भारतीय फिल्म जगत ने अपनी विशिष्ट पहचान के माध्यम से भारतीय संस्कृति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजन की गरिमा को बढ़ाते हुए मोरक्को एंबेसी के सांस्कृतिक अधिकारी वलिद हसबी तथा वियतनाम एंबेसी से प्रो. चु.बाद. क्यू. सहित प्रतिनिधिमंडल ने भी अपनी सहभागिता दर्ज करवाई। इसके अतिरिक्त भारतीय फिल्म जगत की प्रसिद्ध हस्तियां अंजना नाथन, डॉ. बिस्वरूप रॉय चौधरी तथा प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक उमेश शुक्ला भी कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे।

- सिनेमा भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति का प्रतीकः स्वामी ज्ञानानंद
- फिल्म महोत्सव सांस्कृतिक आदान-प्रदान का सशक्त माध्यमः जस्टिस ललित बतरा
- फिल्म जगत ने भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कियाः डॉ. विश्व स्वरूप

फेस्टिवल के डायरेक्टर धर्मेंद्र डांगी एवं उनकी टीम ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। निदेशक धमेन्द्र डांगी ने बताया कि इस चार दिवसीय महोत्सव में 38 देशों की 26 भाषाओं में बनी लगभग 80 चर्चित और प्रशंसित फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें भारत के साथ-साथ वियतनाम और मोरक्को जैसे देशों की फिल्मों को भी प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों और दर्शकों को अंतरराष्ट्रीय सिनेमा से रूबरू होने का अवसर मिलेगा।

कार्यक्रम के दौरान एसडी कॉलेज, पानीपत के विद्यार्थियों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई, वहीं वियतनाम के कलाकारों ने भी अपनी मनमोहक प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

कार्यक्रम का संचालन डीवाएसीए निदेशक प्रो. विवेक चावला, डॉ. सलोनी, पवन दीवान एवं डॉ.आबिद अली द्वारा किया गया।

इस अवसर पर फेस्टिवल के डायरेक्टर धर्मेंद्र डांगी, प्रो. आर.आर. फुलिया, प्रो. सुभाष, प्रो. महावीर, प्रो. सुखवीर, डायरेक्टर-प्रोड्यूसर राजेंद्र यश बाबू, प्रो.शुचिस्मिता, विकास शर्मा, अनूप, सुरेंद्र, डॉ. राजन शर्मा, वेद प्रकाश सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल रहे। साथ ही फिल्म वॉलिंटियर्स श्वेता, अक्षिता, हर्षित, रिया, जश्न, लक्की, सिमरन, प्रकृति, साहिल, निखिल, साक्षी, तेजवीर, ट्विश आदि ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महोत्सव के पहले दिन मुख्य सभागार में पुरस्कार वितरण समारोह, विभिन्न फीचर फिल्मों का प्रदर्शन तथा प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक उमेश शुक्ला की मास्टरक्लास आयोजित की गई। वहीं सीनेट हॉल में विभिन्न देशों के वृत्तचित्रों और अंतरराष्ट्रीय फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।

चार दिवसीय (25-28 मार्च) आठवें हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव-सिनेमा से सरोकार, संस्कृति से प्यारह्व के आगाज हरियाणवी लोककलाकार और पदश्री अवार्डी महावीर गुड्डू के धमाकेदार हरियाणवी गीत की प्रस्तृति के साथ हुआ। इसके साथ ही इंडो-वियतनाम रिश्तों पर आधारित फिल्म वुरों तिन्ह येन प्रेम की सुरधरा, वृत्तचित्र बीम अप यू स्टोरी, गाँव मथान, द टाइडे टुर्न, स्टैड बाई मी, वॉट इज लव का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही वियतनाम के प्रोफेसर चू बाओ कुए की शानदार प्रस्तुति रही।

संपादकीय

ईंधन पर घबराने की जरूरत नहीं! सर्वदलीय बैठक में सरकार ने बताया आगे का प्लान

वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के बीच भारत में ऊर्जा सुरक्षा एक अहम राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में उभरकर सामने आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति श्रृंखलाओं में संभावित व्यवधानों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर स्थिति स्पष्ट की। इस बैठक में सरकार ने सभी राजनीतिक दलों को भरोसा दिलाया कि देश के पास फिलहाल पर्याप्त ऊर्जा भंडार उपलब्ध हैं और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। सरकार का यह आश्वासन ऐसे समय में आया है जब आम जनता, उद्योग जगत और परिवहन क्षेत्र ईंधन की कीमतों और उपलब्धता को लेकर चिंतित हैं। बैठक के माध्यम से सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की कि ऊर्जा आपूर्ति को लेकर किसी तरह की घबराहट की आवश्यकता नहीं है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में बढ़ते तनाव ने अंतरराष्ट्रीय बाजार को अस्थिर बना दिया है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से उतार-चढ़ाव हो रहा है, जिससे आयात-निर्भर देशों पर दबाव बढ़ रहा है। भारत अपनी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है, इसलिए वैश्विक संकट का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सरकार ने इस चुनौती का सामना करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई है। ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण, नए आपूर्तिकताओं से समझौते और दीर्घकालिक अनुबंधों के जरिए आपूर्ति को स्थिर रखने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को भी मजबूत किया गया है ताकि किसी आपात स्थिति में देश को झटका न लगे। सर्वदलीय बैठक का उद्देश्य केवल जानकारी साझा करना नहीं था, बल्कि राजनीतिक सहमति और विश्वास का माहौल बनाना भी था। सरकार ने विपक्षी दलों के सामने ऊर्जा स्थिति की विस्तृत जानकारी रखी और बताया कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की उपलब्धता सामान्य बनी हुई है। विपक्ष ने बैठक में महंगाई और आम लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता जताई। कुछ दलों ने ईंधन की कीमतों में संभावित वृद्धि को लेकर सवाल भी उठाए। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि वह कीमतों को नियंत्रित रखने और आपूर्ति को बाधित न होने देने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। ऊर्जा सुरक्षा का मतलब केवल ईंधन की उपलब्धता नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक नीति ढांचा है जिसमें उत्पादन, वितरण, भंडारण और मूल्य नियंत्रण सभी शामिल हैं। सरकार ने यह भी संकेत दिया कि दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना जरूरी है। भारत ने सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। हरित ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ रहा है और सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय स्रोतों की हिस्सेदारी को काफी बढ़ाया जाए। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरणीय दृष्टि से भी देश को लाभ मिलेगा। ऊर्जा संकट का असर सीधे आम लोगों पर पड़ता है। ईंधन की कीमतों में वृद्धि से परिवहन लागत बढ़ती है, जिससे खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी प्रभावित होती हैं। ऐसे में सरकार का यह आश्वासन कि पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है, बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि केवल अल्पकालिक उपाय पर्याप्त नहीं होंगे। दीर्घकालिक समाधान के लिए ऊर्जा नीति में सुधार, कर ढांचे में पारदर्शिता और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना जरूरी है। इससे न केवल कीमतों को स्थिर रखा जा सकेगा, बल्कि देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी मजबूत होगी। भारत के लिए ऊर्जा क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं, लेकिन संभावनाएं भी कम नहीं हैं। एक ओर जहां आयात पर निर्भरता कम करने की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर नई तकनीकों और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाने का अवसर भी मौजूद है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में ऊर्जा क्षेत्र में बड़े सुधार किए जा सकते हैं। इसमें घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ाना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और हरित हाइड्रोजन जैसी नई तकनीकों में निवेश शामिल हो सकता है। सर्वदलीय बैठक के जरिए सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। यह राष्ट्रीय हित से जुड़ा विषय है, जिसमें सभी दलों की जिम्मेदारी बनती है कि वे रचनात्मक सहयोग दें। यह पहल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक सकारात्मक संदेश देती है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में स्थिर और संगठित है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और वैश्विक मंच पर देश की स्थिति मजबूत होती है। ऊर्जा सुरक्षा आज के समय में केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि रणनीतिक मजबूती का भी प्रतीक बन चुकी है। सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक में दिया गया आश्वासन निश्चित रूप से भरोसा बढ़ाने वाला है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण, नीतिगत सुधार और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करके ही भारत भविष्य में ऊर्जा संकट से पूरी तरह सुरक्षित रह सकता है। आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए कदम और वैश्विक परिस्थितियों के प्रति सतर्क रणनीति ही देश को स्थिर और सशक्त बनाएगी।

हिमाचल प्रदेश में बजट आकार घटने के निहितार्थ

कुलभूषण उपमन्यु (हि.स)

हिमाचल प्रदेश के 2025-26 के बजट का आकार 54,928 करोड़ रुपये है। इससे पहले 2024-25 के बजट का आकार 58,444 करोड़ रुपये और 25-26 के बजट का आकार 58,514 करोड़ रुपये था। जाहिर है कि राजस्व घाटा अनुदान केंद्र सरकार की ओर से बंद हो जाने के कारण महंगाई दर में बढ़ोतरी के बावजूद बजट आकार घटाना पड़ा है। इसका असर विकास योजनाओं पर पड़ना स्वाभाविक है। पेंशन, वेतन, ग्रेच्युटी, ब्याज, ऋण भुगतान, प्रतिबद्ध देनदारियों पर 73.69 प्रतिशत बजट खर्च हो रहा है। इसके चलते वास्तविक विकास कार्यों के लिए केवल 26.31 प्रतिशत भाग ही बचता है।

यह हिमाचल के बजट की स्थाई विसंगति बन चुकी है। यह इस वर्ष भी हावी है। इसके लिए काफी हद तक टॉप हेवी प्रशासन तंत्र का निर्माण बड़ी गलती रहा है, जिसके चलते अनुत्पादक खर्च अनावश्यक रूप से बढ़ गया है। इसके कारण जहां उत्पादक कार्य होना है वहां बजट ही देना संभव नहीं होता है। इसके बावजूद बहुत से जरूरी कार्यों की ओर ध्यान देने का प्रयास किया गया है, हालांकि पर्याप्त धन आवंटन संभव ही नहीं है। कृषि, बागवानी, पशु पालन, वानिकी, के लिए बेहतर पहल करने का प्रयास किया गया है किन्तु पर्याप्त धन आवंटन नहीं हो पाया है। उदाहरण के लिए मानव- वन्य पशु संघर्ष के चलते कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव को रोकने के लिए जालीदार तारबाड़ की बड़े पैमाने पर जरूरत है ताकि सूअर, बंदर, नीलगाय और बेसहारा पशुओं से खेती को पहुंचाया जा रहा नुकसान रुक सके, जिसके चलते बहुत से किसान खेती छोड़ने पर बाध्य हो चुके हैं। खेत बाड़ बंदी योजना पर केवल 10 करोड़ रुपये ही आवंटित किए जा सके जो नाकाफी हैं। पशुपालन क्षेत्र में कई अच्छे फैसले हुए हैं। ए 2 किस्म के दूध को अलग पहचान देने का कार्य सराहनीय है जो भारतीय पशु धन में दूध की गुणवत्ता को मान्यता दे कर प्रोत्साहित करता है।

इसे प्रीमियम कीमत देना भी अच्छा फैसला है। दूध खरीद मूल्य भी किसान हितैषी फैसला है। डेरी उद्योग को पर्याप्त प्रोत्साहन अच्छी पहल है। किन्तु हिमाचल पशु चारे के मामले में पंजाब और हरियाणा के महंगे तूड़ी आयात पर निर्भर हो चुका है जबकि 30- 40 वर्ष पहले जब पशु संख्या आज के मुकाबले बहुत ज्यादा थी हर घर में 2-4 पशु होना मामूली बात थी। आज तो उससे आधे भी पशु नहीं बचे हैं फिर भी तूड़ी आयात करने की बाध्यता वनों से चारा आपूर्ति की क्षमता चीड़ रोपण, और खरपतवारों (लैंटाना, यूपिटोरियम, पार्थेनियुम, नीला फुलनू आदि) के भयानक आक्रमण के कारण इस दौरान समाप्त हो जाने के कारण ही आ पड़ी है। हिमाचल प्रदेश में निजी भूमि तो केवल 10 प्रतिशत ही है। उसमें अन्न, सब्जी, फल, आदि उगाने के बाद बहुत कम चारा उगाने की संभावना बचती है। अतः 67 फीसद वन्य भूमि वाले प्रदेश को वनों से चारा उपलब्ध करवाने की पुरानी क्षमता को हासिल करना होगा, किन्तु इसके लिए चरागाह विकास की कोई योजना आज तक सही तौर पर बनी ही नहीं है। इस बार भी हमने इसकी अनदेखी जारी रखी है। सस्ता चारा पशु पालन का आधार है। इससे पशुपालन लाभदायक बनेगा, तो बेसहारा पशुधन की समस्या भी नियंत्रित होगी। पॉवर टिलर को सब्सिडी देकर प्रोत्साहित किया गया है। इसके कारण बैल तो अब लगभग समाप्त ही हो गया है। सारे बैल तो सड़कों पर घूम रहे हैं। अतः लिंग निर्धारित गभार्धान व्यवस्था पर जोर दिया जाना चाहिए। ताकि ज्यादा तर बछिया ही पैदा हों। इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है।

वनीकरण के लिए 32 फीसद भूमि को वनों के अधीन लाने के लिए महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूहों को जोड़ने की पहल स्वागत योग्य है, किन्तु इसके साथ वन अधिकार कानून के अंतर्गत बनाई गई ग्राम वन प्रबन्धन समितियों को, जहां-जहां ये बन गई हैं, प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये समितियां कानूनी रूप से अधिक सक्षम भी हैं और अधिक स्थाई भी। वन प्रबन्धन के लिए स्थायित्व बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। बागवानी के लिए शिवा परियोजना को चंबा तक विस्तार दिया जाना चाहिए था। चंबा आकांक्षी जिला होने के बावजूद कई पहलों में छूट जाता है।

मछली पर बजट दबाव के बावजूद रायल्टी घटाना अच्छी पहल है। मछली पालन के लिए अन्य सुविधाएं भी स्वागत योग्य हैं। टिकाऊ पर्यटन के लिए नीति और प्रशिक्षण दूर दृष्टि का परिचायक है। हिमाचल में आपदा मुक्त विकास की अवधारणा पर काम करने की अत्यंत आवश्यकता है। पिछले कई वर्षों से हर बरसात में अतिवृष्टि के चलते निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पर्वत विशिष्ट समझ का अभाव दिख रहा है जिस कारण जन-धन की भारी हानि झेलनी पड़ रही है। इस मद पर कोई नीति सामने नहीं आई है। कुल मिला कर बजट सीमित संसाधनों में संतुलन का अच्छा प्रयास है।

(लेखक, हिमालय नीति अभियान के अध्यक्ष और पर्यावरणविद् हैं।)

आज का राशिफल

मेष: आज परिवार में आपके विचारों और सुझावों की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। बिजनेस में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। बच्चों को संस्कार और मार्गदर्शन देने का सही समय है। हालांकि, कार्यक्षेत्र में तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं, जिनसे धैर्यपूर्वक निपटना होगा। *(सिटी दर्पण)*

वृषभ: आज कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव की योजना बना सकते हैं, लेकिन सहयोगियों की वजह से कुछ अड़चनें आ सकती हैं। घरेलू चिंताओं का असर आपके काम पर पड़ सकता है। मानसिक तनाव को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और संयम जरूरी है। *(सिटी दर्पण)*

मिथुन: वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और रिश्तों में तालमेल बेहतर होगा। परिवार और व्यवसाय के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा। राजनीति या सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के लिए दिन शानदार है। व्यापार में साझेदारी से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। *(सिटी दर्पण)*

कर्क: व्यवसाय विस्तार के लिए लिया गया आर्थिक जोखिम सफल हो सकता है। शादी या पारिवारिक आयोजनों के लिए खरीदारी की संभावना है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम जरूरी है। निर्माण और रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े लोगों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। *(सिटी दर्पण)*

सिंह: उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी छवि मजबूत होगी। फिलहाल नौकरी बदलने का समय अनुकूल नहीं है। दोस्तों से मदद लेने में संकोच न करें। युवा वर्ग को इंटरव्यू या करियर अवसरों में सफलता मिल सकती है। सकारात्मक सोच बनाए रखें। *(सिटी दर्पण)*

कन्या: आज कार्यस्थल पर आपकी राय को अपेक्षित समर्थन नहीं मिल सकता। हालांकि, निर्माण कार्यों में प्रगति के योग बन रहे हैं। जरूरी विषयों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। अपने व्यक्तित्व और लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे। *(सिटी दर्पण)*

तुला: अपने सिद्धांतों से समझौता न करें और दूसरों के निजी मामलों से दूरी बनाए रखें। प्रेम संबंधों में भावनाओं को व्यक्त करने का अच्छा अवसर है। राजनीति से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है। संपत्ति विवाद सुलझने के योग बन रहे हैं। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिक: आज खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह फायदेमंद रहेगी। जरूरी कामों में देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य रखें। बड़ी साझेदारी से फिलहाल दूरी बनाए रखें। मौसम में बदलाव के कारण स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। *(सिटी दर्पण)*

धनु: आज आप अपने शौक और रुचियों पर खर्च कर सकते हैं। जीवनसाथी का व्यवहार आपको प्रभावित करेगा। उच्च शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। नए अनुभव और अवसर जीवन में उत्साह बढ़ाएंगे। ऑफिस में अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। *(सिटी दर्पण)*

मकर: आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और भविष्य को लेकर सकारात्मक योजनाएं बनाएंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए दिन अनुकूल है। यात्रा से बचना बेहतर रहेगा। कुछ लोग आपके विचारों से असहमत हो सकते हैं। *(सिटी दर्पण)*

कुंभ: करियर को लेकर युवा वर्ग थोड़ा चिंतित रह सकता है, लेकिन जल्द ही स्थिति बेहतर होगी। प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ेगा। कम प्रयास में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कार्यशैली में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा। *(सिटी दर्पण)*

मीन: आज कार्यक्षेत्र में दबाव कम रहेगा, जिससे राहत मिलेगी। आर्थिक मामलों में फैसले बदल सकते हैं। दिखावे की आदत से बचना जरूरी है, वरना नुकसान हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है। *(सिटी दर्पण)*

श्रद्धा, संकल्प और संस्कारों का महापर्व

प्रतिवर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष नवमी को भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के रूप में रामनवमी का त्यौहार अपार श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जाता है। रामनवमी की तारीख को लेकर इस बार भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल चैत्र महीने के शुक्लपक्ष की नवमी तिथि 26 मार्च को सुबह 11:48 बजे से शुरू होकर अगले दिन 27 मार्च को सुबह 10:06 बजे तक रहेगी। ऐसे में सामान्य जन रामनवमी का पर्व 26 मार्च को मनाएंगे जबकि वैष्णव परंपरा से जुड़े लोग उदया तिथि के आधार पर 27 मार्च को रामनवमी मनाएंगे। रामनवमी के दिन श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या में उत्सव का विशेष आयोजन होता है, जिनमें भाग लेने के लिए देशभर से हजारों भक्तगण अयोध्या पहुंचते हैं । हजारों लोग अयोध्या स्थित सरयू नदी में पवित्र स्नान कर पंचकोसी की परिक्रमा करते हैं। समूची अयोध्या नगरी इस दिन पूरी तरह राममय नजर आती है और हर तरफ भजन-कीर्तनों तथा अखण्ड रामायण के पाठ की गूंज सुनाई पड़ती है। देशभर में अन्य स्थानों पर भी जगह-जगह इस दिन श्रद्धापूर्वक हवन, व्रत, उपवास, यज्ञ, दान-पुण्य आदि विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है।

विभिन्न हिन्दू धर्मग्रंथों में कहा गया है कि श्रीराम का जन्म नवरात्र के अवसर पर नवदुर्गा के पाठ के समापन के पश्चात हुआ था और उनके शरीर में मां दुर्गा की नवीं शक्ति जागृत थी। मान्यता है कि त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या के महाराजा दशरथ की पटरानी महारानी कौशल्या ने मयार्दा पुरुषोत्तम श्रीराम को जन्म दिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार, ह्यह्यभगवान श्रीराम चन्द्रमा के समान अति सुंदर, समुद्र के समान गंभीर और पृथ्वी के समान अत्यंत धैर्यवान थे तथा इतने शील सम्पन्न थे कि दुखों के आवेश में जीने के बावजूद कभी किसी को कटु वचन नहीं बोलते थे। वे अपने माता-पिता, गुरुजनों, भाइयों, सेवकों, प्रजाजनों अर्थात हर किसी के प्रति अपने स्नेहपूर्ण दायित्वों का निर्वाह किया करते थे। माता-पिता के प्रति कर्तव्य पालन एवं आज्ञा पालन की भावना तो उनमें कूट-कूटकर भरी थी। उनकी कठोर से कठोर आज्ञा के पालन के लिए भी वह हर समय तत्पर रहते थे।''

योगेश कुमार गोयल (हि.स)

श्रीराम का चरित्र बेहद उदार प्रवृत्ति का था। उन्होंने उस अहिल्या का भी उद्धार किया, जिसे उसके पति ने देवराज इन्द्र द्वारा छल पूर्वक उसका शीलभंग किए जाने के कारण पतित घोषित कर पत्थर की मूर्ति बना दिया था। जिस अहिल्या को निर्दोष मानकर किसी ने नहीं अपनाया, उसे भगवान श्रीराम ने अपनी छत्रछाया प्रदान की। लोगों को गंगा नदी पार कराने वाले एक मामूली से नाविक केवट की अपने प्रति अपार श्रद्धा व भक्ति से प्रभावित होकर भगवान श्रीराम ने उसे अपने छोटे भाई का दर्जा दिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। अपनी परम भक्त शबरी नामक भीलनी के झूठे बेर खाकर शबरी का कल्याण किया।

महारानी कैकेयी ने महाराजा दशरथ से जब राम को 14 वर्ष का वनवास दिए जाने और अपने लाड़ले पुत्र भरत को राम की जगह राजगद्दी सौंपने का वचन मांगा तो दशरथ गंभीर धर्मसंकट में फंस गए थे। वह बिना किसी कारण राम को 14 वर्ष के लिए वनों में भटकने के लिए भला कैसे कह सकते थे और श्रीराम में तो वैसे भी उनके प्राण बसते थे। दूसरी ओर वचन का पालन करना रघुकुल की मयार्दा थी। ऐसे में जब श्रीराम को माता कैकेयी द्वारा यह वचन मांगने और अपने पिता महाराज दशरथ के इस धर्मसंकट में फंसे होने का पता चला तो उन्होंने खुशी-खुशी उनकी यह कठोर आज्ञा भी सहज भाव से शिरोधार्य की और उसी समय 14 वर्ष का वनवास भोगने तथा छोटे भाई भरत को राजगद्दी सौंपने की तैयारी कर ली। श्रीराम द्वारा लाख मना किए जाने पर भी उनकी पत्नी सीता जी और अनुज लक्ष्मण भी उनके साथ वनों में निकल पड़े।

वनवास की यात्रा की शुरूआत शृंगेवेरपुर नामक स्थान से प्रारंभ कर वहां से वे भारद्वाज मुनि के आश्रम में चित्रकूट पहुंचे। उसके बाद विभिन्न स्थानों की यात्रा के दौरान पंचवटी में उन्होंने अपनी कुटिया बनाने का निश्चय किया। यहीं पर रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटे जाने की घटना हुई। उसी घटना के कारण वहां खर-दूषण सहित 14000 राक्षस राम-लक्ष्मण के हाथों मारे गए। यहीं से श्रीराम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में लंका का राजा रावण माता सीता का अपहरण कर उन्हें अपने साथ लंका ले गया।

कहा जाता है कि जब सीता का विरह श्रीराम से नहीं सहा गया तो उन्होंने साधारण मनुष्य की भांति विलाप किया लेकिन हिम्मत न हारते हुए सीता जी की खोज में राम-लक्ष्मण जंगलों में भटकने लगे। इसी दौरान उनकी भेंट श्रीराम के अनन्य भक्त हनुमान से हुई, जिन्होंने राम-लक्ष्मण को वानरराज बाली के छोटे भाई सुग्रीव से मिलाया, जो उस समय बाली के भय से यहां-वहां छिपता फिर रहा था। श्रीराम ने बाली का वध करके सुग्रीव तथा बाली के पुत्र अंगद को किष्किंधा का शासन सौंपा और उसके बाद सुग्रीव की वानरसेना के नेतृत्व में लंका पर आक्रमण कर देवताओं पर भी विजय पाने वाले महाप्रतापी, महाबली, महापंडित तथा भगवान शिव के घोर उपासक लंका नरेश राक्षसराज रावण का वध कर सीता को उसके बंधन से मुक्त कराया और लंका पर खुद अपना अधिकार न जमाकर लंका का शासन रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया तथा वनवास की अवधि समाप्त होने पर भैया लक्ष्मण, सीता जी व हनुमान सहित अयोध्या लौट आए। वास्तव में विधि के विधान के अनुसार राम को दुष्ट राक्षसों का विनाश करने के लिए ही वनवास मिला था।

उन्होंने अपने मानव अवतार में न तो भगवान श्रीकृष्ण की भांति रासलीला खेली और न ही कदम-कदम पर चमत्कारों का प्रदर्शन किया बल्कि उन्होंने सृष्टि के समक्ष अपने क्रियाकलापों के जरिये ऐसा अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसकी वजह से उन्हें ह्यमयार्दा पुरुषोत्तम' कहा गया। जहां तक राम-रावण के बीच हुए भीषण युद्ध की बात है तो वह सिर्फ दो राजाओं के बीच का सामान्य युद्ध नहीं बल्कि दो विचारधाराओं का संघर्ष था, जिसमें एक मानव संस्कृति थी तो दूसरी राक्षसी संस्कृति। एक ओर क्षमादान की भावना को महत्व देने वाले व जनता के दुख-दर्द को समझने एवं बांटने वाले वीतरागी भाव थे तो दूसरी ओर दूसरों का सब कुछ हड़प लेने की राक्षसी प्रवृत्ति।

रावण अन्याय, अत्याचार व अनाचार का प्रतीक था तो श्रीराम सत्य, न्याय एवं सदाचार के। यही नहीं, सीता जी के अपहरण के बाद भी श्रीराम ने अपनी मयार्दाओं को कभी तिलांजलि नहीं दी। उन्होंने इसके बाद भी रावण को एक महाज्ञानी के रूप में सदैव सम्मान दिया और यह इससे साबित भी हुआ कि रावण की मृत्यु से कुछ ही क्षण पूर्व श्रीराम ने लक्ष्मण को रावण के पास ज्ञान अर्जन के लिए भेजा था। मयार्दा पुरुषोत्तम श्रीराम में सभी के प्रति प्रेम की अगाध भावना कूट-कूटकर भरी थी। उनकी प्रजा वात्सल्यता, न्यायप्रियता और सत्यता के कारण ही उनके शासन को आज भी ह्यआदर्श' शासन की संज्ञा दी जाती है और आज भी अच्छे शासन को ह्यरामराज्य' कहकर परिभाषित किया जाता है। ह्यरामराज्य' यानी सुख, शांति एवं न्याय का राज्य। रामनवमी पर्व वास्तव में मयार्दा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की गुरु सेवा, माता-पिता की सेवा व आज्ञापालन, जात-पात के भेदभाव को मिटाने, क्षमा शीलता, भ्रातृ प्रेम, पत्नी व्रता, न्याय प्रियता आदि विभिन्न महान आदर्शों एवं गुणों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

मोहन सरकार का संवेदना से सशक्तिकरण तक का निर्णय है दिव्यांग शिक्षा में मानदेय वृद्धि

डॉ. मयंक चतुर्वेदी (हि.स)

समाज की वास्तविक प्रगति का मापदंड इस बात से तय होता है कि वह अपने सबसे कमजोर वर्गों के प्रति कितना संवेदनशील है। 'दिव्यांगजन' वे लोग हैं, जो जन्म से या जीवन की किसी दुर्घटना के कारण शारीरिक या मानसिक सीमाओं से जूझते हैं, परंतु उनके सपने, उनकी आकांक्षाएं और उनका आत्मसम्मान किसी भी सामान्य व्यक्ति से कम नहीं होता। ऐसे में जब डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए 18 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय स्वीकृत किया, तब यह निश्चित तौर पर संवेदनशील शासन का जीवंत उदाहरण बन गया है। वस्तुतः यह निर्णय उन अनगिनत शिक्षकों और बच्चों के जीवन में आशा की नई किरण लेकर आया है, जोकि वर्षों से उपेक्षा और संघर्ष का सामना कर रहे थे।

देखाजाए तो 'दिव्यांगता' को अक्सर शारीरिक अक्षमता के रूप में देखा जाता है, जबकि यह उससे कहीं अधिक व्यापक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चुनौती है। एक दिव्यांग व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में हर कदम पर बाधाओं का सामना करना पड़ता है; चाहे वह शिक्षा हो, रोजगार हो या सामाजिक स्वीकृति। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व की लगभग 15 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी रूप में 'दिव्यांगता' से प्रभावित है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि यह कोई सीमित वर्ग न होकर एक बड़ा वैश्विक समुदाय है, जिसकी उपेक्षा मानवता के साथ अन्याय के समान है।

भारत और मध्य प्रदेश की स्थिति

भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 2.21 प्रतिशत लोग दिव्यांग हैं, विशेषज्ञ मानते हैं कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। मध्य प्रदेश में भी यह प्रतिशत लगभग दो के आसपास है, जो लाखों लोगों के जीवन की वास्तविकता को दशार्ता है। इन आंकड़ों के पीछे छिपी सच्चाई एक यह भी है कि इन लाखों लोगों में अनेकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। ऐसे में यदि सरकार इनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देती है, तब अवश्य ही सीधे उनके जीवन की दिशा बदलने जैसा बदलाव समय के साथ देखने को मिलता है।

यह हमें स्वीकारना ही होगा कि एक दिव्यांग बालक या बालिका को शिक्षित करना सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण, धैर्य, तकनीकी साधनों और व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता होती है। एक चुनौतीपूर्ण है। इन परिस्थितियों में कहना होगा कि शिक्षकों का योगदान सेवा और समर्पण का अनुपम उदाहरण के रूप में सामने आता है।

शिक्षक बदलाव के वास्तविक नायक हैं

दिव्यांग शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक समाज के अनदेखे नायक होते हैं। वे बच्चों को अक्षरज्ञान कराने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनने का साहस और आत्मविश्वास भी प्रदान करते हैं। वे हर दिन उन सीमाओं को चुनौती देते हैं, जिन्हें समाज ने 'असंभव' मान लिया है। किंतु जब लंबे समय तक इन्हीं शिक्षकों को कम मानदेय और अस्थिरता का सामना करना पड़ता है तब स्वभाविक है कि उनके मनोबल और इस क्षेत्र की गुणवत्ता दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही है।

आज आप कह सकते हैं कि इस स्थिति में मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन सरकार द्वारा 18 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय देने का निर्णय इस स्थिति को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ ही शिक्षकों के कार्य को मान्यता और सम्मान भी देता है। यह तो सर्वमान्य बात है कि जब किसी शिक्षक को उसके कार्य के अनुरूप पारिश्रमिक मिलता है, तब वह अधिक समर्पण और ऊर्जा के साथ कार्य करता है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में भी स्वाभाविक रूप से सुधार होता है।

इस निर्णय का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इससे दिव्यांग शिक्षा के क्षेत्र में योग्य और प्रशिक्षित लोगों को आकर्षित किया जा सकेगा। पहले कम वेतन के कारण इस क्षेत्र में आने से लोग हिचकिचाते थे, किंतु अब बेहतर मानदेय मिलने से यह क्षेत्र अधिक आकर्षक बन सकेगा। इससे इस क्षेत्र में शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी और उनकी गुणवत्ता भी बेहतर होगी, जिसका सीधा लाभ बच्चों को मिलेगा।

समावेशी समाज की ओर मजबूत कदम

इसका एक पहलु ये भी है कि यह निर्णय सिर्फ शिक्षकों तक सीमित नहीं है, यह एक समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में उठाया गया कदम है। जब दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी तो वे भी समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगे। वे आत्मनिर्भर बनेंगे, रोजगार प्राप्त करेंगे और समाज में अपनी पहचान स्थापित करेंगे। यही किसी भी विकसित समाज की पहचान होती है।

मोहन सरकार की इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह दिव्यांगता के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव को दशार्ती है। अब दिव्यांगजन को दया या सहानुभूति के पात्र के रूप में न देखकर अधिकार और अवसर के हकदार नागरिक के रूप में देखा जा रहा है। यह सोच आधुनिक और प्रगतिशील शासन की पहचान है और यही वास्तविक सामाजिक न्याय की नींव है।

अतः दिव्यांग शिक्षा में मानदेय वृद्धि, कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार वह निर्णय है जोकि एक सकारात्मक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है; वस्तुतः एक ऐसी विचारधारा, जिसमें हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान देने की प्रतिबद्धता है। यह निर्णय आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत और समावेशी समाज की नींव रखेगा। फिलहाल मोहन सरकार के इस निर्णय से यही आशा है।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना पंजाबियों के लिए 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का वरदान साबित हुई : डॉ. बलबीर सिंह

कहा- युद्ध नशों के विरुद्ध के तहत नशों की मांग घटाकर नशा पीड़ितों के इलाज के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़ /पटियाला

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की अनूठी योजना मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना पंजाबियों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने आज यहां स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछले चार वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि इस योजना के तहत अब तक 1.60 लाख लोगों ने 191 करोड़ रुपये का मुफ्त इलाज करवाया है।

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि आज पंजाब के स्वास्थ्य मॉडल की देश के अन्य राज्यों में भी नकल होने लगी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सरकार ने चार वर्षों में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता दी है, जिसके परिणाम सबके सामने हैं।

उन्होंने कहा कि पटियाला के सरकारी राजिंदरा अस्पताल और माता कौशल्या अस्पताल के कायाकल्प से राज्य में स्वास्थ्य क्रांति की शुरूआत हुई और पिछले चार वर्षों में सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 65 लाख परिवारों और 3 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाने हैं, जिनमें से अब तक 25 लाख कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी बीमारी का इंतजार करने के बजाय पहले ही अपने स्वास्थ्य कार्ड बनवा लें।

उन्होंने बताया कि राज्य में 9 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिनमें फतेहगढ़ साहिब और ईएसआई लुधियाना पहले ही शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा होशियारपुर, कपूरथला, संगरूर, शहीद भगत सिंह नगर, लहरागागा, मलेरकोटला और लुधियाना में बन रहे मेडिकल कॉलेजों में 600 नई एमबीबीएस सीटें जोड़ी जाएंगी। साथ ही मेडिकल शिक्षा विभाग में मानव संसाधन की कमी दूर करते हुए प्रोफेसरों को पदोन्नति दी गई है।

डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 200 करोड़ रुपये के उपकरण खरीदे जा रहे हैं तथा राज्य के सभी जिलों में 50-50 बिस्तरों वाले 22 क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मुफ्त दवाइयों के साथ-साथ डायग्नोस्टिक सेवाओं का

विस्तार किया जा रहा है। इस वर्ष सभी जिला अस्पतालों में एमआरआई, 8 अन्य अस्पतालों में सीटी स्कैन सुविधाएं शुरू की जाएंगी। इसके अलावा 250 बिस्तरों वाले 7 मातृ एवं शिशु अस्पताल शुरू किए जाएंगे और एक्स-रे व अल्ट्रासाउंड के लिए 200 से अधिक सूचीबद्ध निजी डायग्नोस्टिक केंद्र भी कार्यरत हैं।

उन्होंने बताया कि 5 जिलों में एआई आधारित स्क्रीनिंग के तहत 9294 महिलाओं की जांच में 8 स्तन कैंसर और 43 सर्वाइकल कैंसर के मामले सामने आए, जबकि एआई आधारित आंखों की जांच में 1.07 लाख लोगों में से 21,660 में दृष्टि संबंधी समस्याएं पाई गईं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान के तहत जहां नशों की मांग घटाकर सप्लाई चेन तोड़ी गई है, वहीं नशा पीड़ितों के मुफ्त इलाज के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा भी उपलब्ध कराया गया है। साथ ही उनके कौशल विकास के लिए नई व्यवस्थाएं की गई हैं और जेलों में भी क्लीनिकों का विस्तार किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि राज्य में 883 आम आदमी क्लीनिकों ने 5 करोड़ ओपीडी के माध्यम से 1.69 करोड़ लोगों का मुफ्त इलाज किया है। सीएम की योगशाला परियोजना के तहत 8000 योग सत्रों से प्रतिदिन 2 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा 948 जनरल डॉक्टर और 627 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती की गई है, जो राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी मेडिकल भर्ती है।

डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि जल्द ही पटियाला, अमृतसर और फरीदकोट के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आईवीएफ तथा मोहाली में पीईटी स्कैन सुविधा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही कोक्लियर इम्प्लांट, लिवर व किडनी ट्रांसप्लांट तथा दिल, दिमाग और रीढ़ की सर्जरी भी इन अस्पतालों में की जा रही है।

उन्होंने बताया कि सरकारी राजिंदरा अस्पताल के सभी ऑपरेशन थिएटर आधुनिक मॉड्यूलर बनाए जा चुके हैं और यहां ट्रॉमा सेंटर भी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के 3 करोड़ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि सरकारी अस्पताल किसी भी निजी अस्पताल से कम न हों।

डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि दिल के दौरे के मरीजों को समय पर इलाज देने के लिए 23 जिलों में मिशन अमृत स्टेमी परियोजना शुरू की गई है। इसके तहत 29,000 लोगों को पंजीकृत किया गया और 800 मरीजों का आपातकालीन हृदय उपचार किया गया।

उन्होंने बताया कि पंजाब स्ट्रोक परियोजना के तहत एआई आधारित स्टोक प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है, जिससे अब तक 100 मरीजों को लाभ मिला और 40 का उपचार किया गया। इसके अलावा टेली-मानस सेवा के तहत टोल-फ्री नंबर 14416 पर मानसिक स्वास्थ्य सहायता भी प्रदान की जा रही है।

भगवंत मान सरकार कर्मचारियों की शिकायतों को शीघ्र और निष्पक्ष तरीके से हल करने के लिए प्रतिबद्ध: हरपाल चीमा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन के रूप में आज पंजाब भर की विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों की लंबित मांगों और चिंताओं को हल करने के लिए अपने कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठकें कीं।

इन बैठकों के दौरान वित्त मंत्री ने मेरिटोरियस स्कूल टीचर्स यूनियन, अध्यापक इंसाफ कमेटी, फायर ब्रिगेड आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन, फायर ब्रिगेड कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी यूनियन तथा जंगलात विभाग वर्कर्स यूनियन सहित कई यूनियनों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ सीधी बातचीत की।

वित्त मंत्री ने संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उनके मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की और यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए कि यूनियनों द्वारा उठाई गई सभी जायज मांगों पर जल्द से जल्द विचार कर उनका समाधान किया जाए। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कर्मचारियों के कल्याण को सुरक्षित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि उनकी जायज मांगों को समयबद्ध तरीके से हल किया जाए।

भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि कैबिनेट सब-कमेटी कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली के माध्यम से उनकी चिंताओं को सुना और हल किया जाए।

इन बैठकों के दौरान मेरिटोरियस स्कूल टीचर्स यूनियन से डॉ. टीना और अजय कुमार, अध्यापक इंसाफ कमेटी से विक्रम देव सिंह, दिग्विजय पाल शर्मा, सुखविंदर सिंह चाहल और बाज सिंह, फायर ब्रिगेड आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन से साहिब सिंह, गुरविर्यम सिंह और सुखजीत सिंह, फायर ब्रिगेड कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी यूनियन से सोभा सिंह, तथा जंगलात वर्कर्स यूनियन से मख्खन सिंह वाहिदपुरी, अमरीक सिंह, जसविंदर सिंह, सतनाम सिंह, रवि कुमार और शिंदरपाल सिंह ने अपनी-अपनी यूनियनों के मुद्दे प्रस्तुत किए।

महिलाओं की सेहत और सम्मान के लिए बड़ा कदम

सिटी दर्पण संवाददाता
अमृतसर

पंजाब सरकार ने 127.95 करोड़ रुपये सीधे खातों में किए ट्रांसफर, 2.89 लाख से अधिक माताओं को राहत

अमृतसर में जिला लोक संपर्क कार्यालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, पंजाब सरकार ने महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए बड़ी वित्तीय सहायता जारी की है।

इस संबंध में जिला योजना समिति अमृतसर के चेयरमैन गुरप्रताप सिंह संधू ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक कुल 127.95 करोड़ रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजी गई है। इससे लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के सहायता प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान 2.89 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है। यह पहल न केवल आर्थिक मदद है, बल्कि माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच भी है, जिससे हजारों परिवारों में विश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ी है। योजना के तहत पहले बच्चे के लिए महिलाओं को दो किस्तों (3000+2000 रुपये) में कुल 5000 रुपये की राशि दी जाती है। वहीं, यदि दूसरा बच्चा बेटी हो, तो लाभार्थी महिला को एकमुश्त 6000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है, जो बेटी के जन्म को प्रोत्साहित करने की दिशा में अहम कदम है।

संक्षिप्त-समाचार

भारत में जूनियर गोल्फ को बढ़ावा देने के लिए डीपी वर्ल्ड ने जेन गोल्फ में नया क्लबहाउस खोला

चंडीगढ़। डीपी वर्ल्ड ने गुरुग्राम स्थित जेन गोल्फ रेंज एंड एकेडमी में परमानेंट क्लबहाउस खोलने का एलान किया। हीरो इंडियन ओपन (26 से 29 मार्च) के ठीक पहले उठाए गए इस कदम के साथ कंपनी ने जमीनी स्तर पर गोल्फ को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूती दी है। यह क्लबहाउस डीपी वर्ल्ड के ग्लोबल क्लबहाउस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दूसरा क्लबहाउस है। इससे पहले 2025 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पहला क्लबहाउस खोला गया था। लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में डीपी वर्ल्ड की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए प्रत्येक क्लबहाउस को एक रीपर्पज्ड शिपिंग कंटेनर से तैयार किया गया है। इसे स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहां गोल्फ इक्विपमेंट एवं शेल्टर्ड ट्रेनिंग एरिया मिलेगा। इससे एक सुरक्षित एवं समर्पित जगह मिलेगी, जहां युवा अपनी काबिलियत एवं कौशल को निखार सकेंगे। दुबई में एक लोकल पोर्ट ऑपरेटर से ग्लोबल सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर बनने तक के डीपी वर्ल्ड के सफर में गोल्फ का महत्वपूर्ण जुड़ाव रहा है। जैसे-जैसे वैश्विक स्तर पर कारोबार का विस्तार हो रहा है, विभिन्न बाजारों में ग्राहकों, पार्टनर्स एवं स्टेकहोल्डर्स को जोड़ने के लिए गोल्फ एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन गया है। डीपी वर्ल्ड के ग्रुप चीफ कम्युनिकेशंस ऑफिसर डेनियल वैन ओटेरडिज ने कहा कि वैश्विक स्तर पर खेलों के हमारे सफर में भारत महत्वपूर्ण सहभागी है। यहां परमानेंट क्लबहाउस खोलना इस खेल की नींव को मजूबत करने की हमारी प्रतिबद्धता दिखाता है। हम गोल्फर्स की नई पीढ़ी का सहयोग कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह खेल वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़े।

फ्रंटियर बिस्किट ने चंडीगढ़ में अपना फ्रेंचाइजी आउटलेट किया शुरू

चंडीगढ़। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष पहचान बना चुके फ्रंटियर बिस्किट ने अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार करते हुए चंडीगढ़ में भी पर्दापण किया है। कंपनी ने चंडीगढ़ में अपना फ्रेंचाइजी आउटलेट की शुरूआत करते हुए चंडीगढ़ सेक्टर 23 स्थित अग्रणी रिटेल आउटलेट मेसर्स चुन्नी लाल मोहन लाल पर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज को प्रस्तुत किया है। इस अवसर पर चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव चड्ढा की टीम सहित गुरशरण बत्रा, राधेलाल बजाज, रविंदर सिंह बिल्ला, बलविंदर सिंह, बलजिंदर गुजरात और अवनीश बंसल सहित संजीव अग्रवाल व अन्य भी उपस्थित थे। फ्रंटियर बिसकिट्स के जनरल मैनेजर प्रीत मोहिन्दर सिंह ने बताया कि फ्रंटियर बिसकिट्स 1921 की स्थापित कंपनी है व 105 वर्ष पुरानी कंपनी है और मूलतः पाकिस्तान से है। राजन सेठी जी द्वारा संचालित यह कंपनी की चौथी पीढ़ी हैं जो अब इस विरासत को आगे लेकर जा रहे हैं। दिल्ली के नारायणा से ऑपरेटिव फ्रंटियर बिसकिट्स ने देश के प्रमुख राज्यों व शहरों में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद अब चंडीगढ़ की तरफ रुख किया है

उत्तरी भारत की पहली फ्रैंचाइजी पिकलबॉल लीग की घोषणा चंडीगढ़ में हुई

चंडीगढ़। उत्तरी भारत उभरते खेलोंके विकास में एक अहममील का पत्थर स्थापितकरने के लिए पूरीतरह तैयार है, क्योंकि यहां टायनॉर नॉर्थे इंडिया पिकलबॉल कप (एनआईपीसी) 2026 -सीजन1 की आधिकारिक घोषणा की गई है।उत्तरी भारत की पहलीफ्रैंचाइजी-शैली वाली पिकलबॉललीग के तौर परे पेश किया जा रहायह टूनार्मेंट 11-12 अप्रैल, 2026 को मोहाली केपरवाज स्पोर्ट्स में आयोजित कियाजाएगा। यह बताना जरूरी है कि पिकलबॉलएक तेजी से बढ़ता हुआपैडल खेल है, जिसमेंटेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिसके एलिमेंट्स शामिल होते हैं। इसेआम तौरे परे एकछोटे कोर्ट पर नेट केसाथ खेला जाता है,जिसमें ठोस पैडल औरएक हल्का, छेद वाला प्लास्टिकका गेंद इस्तेमाल होताहै। यह खेल सिंगल्सया डबल्स फॉर्मेटे में खेला जासकता है। मैच आमतौर पर 11 अंकों तक खेले जातेहैं, और जीतने केलिए दो अंकों कीबढ़त जरूरी होती है। ए.जे. सिंह, डायरेक्टर,टायनॉर ऑर्थोटिक्स ने एनआईपीसी केसाथ अपने जुड़ाव केजरिए फिटनेस, कम्युनिटी सहभागिता और खेल मेंबेहतरीन प्रदर्शन को बढ़ावो देनेके लिए ब्रांड कीप्रतिबद्धता पर जोर दिया।सिंह ने कहा कि एनआईपीसी का लक्ष्य खिलाड़ियों,फ्रैंचाइजी, ब्रांड्स और कम्युनिटीज कोएक साथ लाकर एके लंबे समय तक चलनेवाला, प्रोफेशनल पिकलबॉल इकोसिस्टम बनाना है।

डीएवी पब्लिक स्कूल, सेक्टर-8, पंचकूला ने वार्षिक समारोह नवांकुर भव्यता के साथ मनाया

चंडीगढ़/पंचकूला। डीएवी पब्लिक स्कूल, सेक्टर-8, पंचकूला ने अपना वार्षिक समारोह नवांकुर आयोजित किया, जिसमें छात्रों की उभरती प्रतिभा और समग्र विकास का उत्सव मनाया गया। यह कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ और इसमें विशिष्ट अतिथियों, अभिभावकों तथा डीएवी परिवार के सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम की शुरूआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन से हुई, जो ज्ञान और प्रकाश की विजय का प्रतीक है। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों में डीसीपी पंचकूला, डीईओ पंचकूला, बीईओ पंचकूला, स्कूल के चेयरमैन एवं वाइस चेयरमैन, मैनेजर मैडम, रीजनल असिस्टेंट-कम-क्लस्टर हेड तथा अन्य प्रतिष्ठित अतिथि शामिल थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरूआत मंगलाचरण और डीएवी गान से हुई, जिसमें समारोह की सफलता के लिए ईश्वरीय आशीर्वाद मांगा गया। इसके बाद मंच पर छात्रों की रंगारंग और मनमोहक प्रस्तुतियों ने माहौल जीवंत कर दिया। जीवंत नृत्य, विषय-आधारित प्रस्तुतियों और संगीत के माध्यम से युवा कलाकारों ने अपना आत्मविश्वास, सृजनशीलता और कलात्मक उत्कृष्टता प्रदर्शित की। नवांकुर थीम-नई शुरुआत और युवा मन की खिलती संभावनाओं का प्रतीक-प्रस्तुतियों में खूबसूरती से दर्शाई गई। प्रस्तुतियों में संस्कृति और देशभक्ति के मूल्यों का प्रतिबिंब देखने को मिला, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

पंजाब पुलिस ने दुष्कर्म व अन्य आरोपों से घिरे आआपा विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया

चंडीगढ़। पंजाब पुलिस ने दुष्कर्म व अन्य आरोपों से घिरे सनौर हलके से आम आदमी पार्टी (आआपा) विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को मध्य प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया है। पठानमाजरा कई माह से फरार थे। एक सितंबर 2025 को पंजाब के पटियाला के सिविल लाइंस थाने में एक महिला द्वारा

बलात्कार, धोखाधड़ी व अन्य आरोपों के तहत हरमीत सिंह पठानमाजरा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि 2013-2014 से लेकर 2024 तक (विशेष रूप से 12 फरवरी 2014 से 12 जून 2024 तक) पठानमाजरा ने शादी का झांसा देकर, खुद को तलाकशुदा बताकर शारीरिक संबंध बनाए। 2021 में लुधियाना के एक गुरुद्वारे में उनकी शादी भी हुई, लेकिन पठानमाजरा पहले से शादीशुदा थे। इसके बाद 2 सितंबर को हरियाणा के करनाल में पठानमाजरा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस हिरासत से फायरिंग और पथराव की आड़ में वह फरार हो गए थे। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हुआ था। इसके बाद यह मामला अदालत पहुंचा था। दिसंबर 2025 में पटियाला कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। इसके बाद खबर आई कि वह ऑस्ट्रेलिया भाग गए हैं और वहां से इंटरव्यू भी दिए। तब कोर्ट ने लुकआउट नोटिस जारी किया। पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा ने बताया कि मंगलवार देर रात उन्हें मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास शिवपुरी जिले में दबोचा गया। आरोपित विधायक के साथ उनके तीन साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपित को पटियाला ले आया गया है।

तरुनप्रीत सिंह सौंद द्वारा युवाओं से राष्ट्र निर्माण के लिए शहीद-ए-आजम भगत सिंह के पदचिह्नों पर चलने की अपील

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब राज्य खाद्य आयोग द्वारा आज पंजाब कला भवन, चंडीगढ़ में शहीद-ए-आजम स भगत सिंह के शहीदी दिवस को अत्यंत श्रद्धा, जोश और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पंजाब के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों, ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री स तरुनप्रीत सिंह सौंद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।

सभा को संबोधित करते हुए स सौंद ने कहा कि शहीद-ए-आजम स भगत सिंह के आदर्श सदैव समाज को न्याय, समानता और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देते रहेंगे। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए शहीदों के पदचिह्नों पर चलते हुए पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ आगे आएं।

उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक मंचों की भूमिका शहीदों की गौरवशाली विरासत को संरक्षित करने और सामूहिक पहचान को मजबूत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि शहीदों का संदेश युवाओं को अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने, ज्ञान अर्जित करने और देश की प्रगति में ईमानदारी से योगदान देने के लिए प्रेरित करता है।

इस दौरान पंजाब राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन श्री बाल मुकंद शर्मा ने आयोग की पहलों का उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य भर में खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को संतुलित आहार और टिकाऊ जीवनशैली के प्रति जागरूक करने के लिए 5723 स्कूलों में न्यूट्रिशन गार्डन स्थापित किए गए हैं।

समारोह के दौरान वक्ताओं ने शहीद-ए-आजम स भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन साहस, बौद्धिक चेतना और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। उनकी विचारधारा आज भी युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनने और लोकतांत्रिक मूल्यों एवं भाईचारे को बनाए रखने की प्रेरणा देती है।

इस अवसर पर आयोग के सदस्य जसवीर सिंह सेखों, विजय दत्त और चेतन प्रकाश धालीवाल, पूर्व सदस्य प्रीति चावला और इंदिरा गुप्ता तथा सदस्य सचिव कनु ठिंद भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना यह सुनिश्चित करती है कि वित्तीय या प्रशासनिक बाधाओं के कारण इलाज में देरी न हो: डॉ. बलबीर सिंह

भगवंत सिंह मान की पहल पर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत बीमारी से जूझ रही 1 वर्षीय बच्ची को मिला जीवनरक्षक इलाज

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत इलाज प्राप्त करने वाले नवजात और छोटे बच्चों की बढ़ती संख्या के साथ, भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि नाजुक समय में चिकित्सा सहायता बिना किसी देरी के शुरू हो।

श्री मुक्तसर साहिब में 1 साल की बच्ची ख्वाहिश को निमोनिया के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसे तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। पहले ऐसे कई मामलों में परिवारों को इलाज शुरू होने से पहले धन की व्यवस्था करना, दस्तावेज पूरे करना या मंजूरी का इंतजार करना पड़ता था। हालांकि, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत इस अंतर को समाप्त कर दिया गया है।

स्वास्थ्य कार्ड पहले से बना होने के कारण दीप अस्पताल में डॉ. मोनिका गर्ग की निगरानी में बिना किसी अग्रिम भुगतान के तुरंत इलाज शुरू कर दिया गया।

परिवार को न तो पैसों की व्यवस्था करनी पड़ी और न ही सत्यापन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, जिससे डॉक्टरों को नाजुक समय में इलाज शुरू करने में मदद मिली। छोटे बच्चों के मामलों में थोड़ी सी देरी भी जटिलताएं पैदा कर सकती है, लेकिन उपचार तक त्वरित पहुंच ने यह सुनिश्चित किया कि बच्ची को समय पर देखभाल मिली और वह सुरक्षित रूप से स्वस्थ हो गई।

इसी तरह के मामले संगरूर और मानसा जैसे जिलों से भी सामने आए हैं,

जहां कम वजन और अन्य गंभीर स्थितियों से जूझ रहे नवजातों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, और उन्हें बिना किसी वित्तीय बाधा के योजना के तहत चिकित्सा सहायता मिल रही है। ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या यह दर्शाती है कि पूरे पंजाब में परिवारों के लिए इलाज तक पहुंच कितनी तेज और आसान हो रही है।

योजना के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यह योजना सुनिश्चित करती है कि वित्तीय या प्रशासनिक बाधाओं के कारण इलाज में कोई देरी न हो। ऐसे मामलों में, जहां छोटे बच्चों को तत्काल देखभाल की आवश्यकता होती है, थोड़ी सी देरी भी गंभीर परिणाम दे सकती है। यह योजना उस खतरे को पूरी तरह समाप्त कर देती है।

यह योजना प्रति परिवार प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, जिससे सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज कराया जा सकता है। अब तक 26 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं और मरीज 900 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में 2300 से अधिक मेडिकल पैकेजों के तहत उपचार प्राप्त कर रहे हैं।

योजना के अंतर्गत नवजात और बाल चिकित्सा मामलों की बढ़ती संख्या तेज और अधिक सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में बदलाव को दर्शाती है, जहां इलाज बिना किसी वित्तीय झिझक के शुरू होता है। पंजाब सरकार निवासियों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत कैशलेस उपचार का लाभ उठाने के लिए निर्धारित केंद्रों पर स्वास्थ्य कार्ड के लिए पंजीकरण कराने हेतु लगातार प्रोत्साहित कर रही है।

ईरान में बमबारी, स्कूल उड़ा, इजराइल में बज रहे सायरन, लेबनान में हमला

मध्य-पूर्व में महायुद्ध की आहट: ईरान-इजरायल संघर्ष में कूदा अमेरिका

एजेंसी (हि.स.)
तेहरान/बेरुत/वाशिंगटन

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच 28 फरवरी से छिड़ा युद्ध दिन-ब-दिन विस्तार लेता जा रहा है। इस युद्ध की विभीषिका में खाड़ी देश भी झुलस रहे हैं। तेल और गैस के लिए निर्भर दुनिया के बाकी देशों में अलग तरह का संकट खड़ा हो गया है। ईरान और इजराइल के साथ लेबनान के आसमान पर मिसाइलें गरज रही हैं। ईरान में हुई बमबारी में एक स्कूल उड़ गया है। इजराइल के मध्य में सायरन बज रहे हैं। लेबनान में रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं। इस सबके बीच अमेरिकी रक्षा मुख्यालय (पेंटागन) ने संकेत दिए हैं कि मध्य-पूर्व में 82वीं एयरबोर्न टुकड़ियों (पैराट्रूप्स) को भेजे जाने की हरी झंडी मिल गई है।

पेंटागन ने 82वीं एयरबोर्न टुकड़ी को दी हरी झंडी

अल जजीरा, द टाइम्स ऑफ इजराइल और सीबीएस न्यूज की अलग-अलग रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, आज तड़के ईरान की राजधानी के पूरब में धमाकों की आवाज सुनी गई है और चल रही बमबारी में रिहायशी इमारतें और एक स्कूल तबाह हो गया है। उधर, इजराइल की सेना ने ईरान से देश के मध्य हिस्सों की ओर दागे गए प्रोजेक्टाइल का पता लगाया है। इस हमले के बाद पूरे मध्य इजराइल में हवाई हमले के अलार्म बज उठे।

ईरान और हिजबुल्लाह ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव और उत्तरी इलाकों में मिसाइल हमला किया है।

फोटोः हि.स.

हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम एक दर्जन लोग घायल हो गए। इजराइली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। खबरों में बताया गया है कि इराकी समूह इस्लामिक रेजिस्टेंस ने पिछले 24 घंटों में अमेरिकी ठिकानों पर 23 हमलों का दावा किया है। यह समूह ईरान-समर्थित मिलिशिया का नेटवर्क है। इसमें शक्तिशाली समूह कताइब हिजबुल्लाह भी शामिल है।

बताया जा रहा है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद फ्यूल टैंक में आग लग गई। कुवैत सिविल एविएशन प्राधिकरण ने इसकी पुष्टि की है। जॉर्डन की राजधानी अमान के दक्षिण में कम आबादी वाले इलाके में मिसाइल के टुकड़े गिरने की सूचना है। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने देश के पूर्वी प्रांत में एक बैलिस्टिक मिसाइल और कम से कम छह ड्रोन को मार गिराया। इजराइल के उत्तर में कीर्यात श्मोना शहर और आसपास के क्षेत्रों में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई है।

सीबीएस न्यूज ने अमेरिकी रक्षा विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से कहा है कि अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने पैराट्रूप्स को भेजने का फैसला किया है। दावा किया गया है कि पेंटागन सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के जांबाज जवानों को मध्य पूर्व भेजेगा। यह भी कहा जा रहा है कि यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उप राष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर (राष्ट्रपति के दामाद) ने लंबी चर्चा के बाद लिया। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य के न खुलने पर चिंता जताई है।

ईरान से नेपाली नागरिक अमृत झा की रिहाई के लिए कूटनीतिक पहल

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

ईरानी सुरक्षा बलों के नियंत्रण में रखे गए नेपाली नागरिक अमृत झा से मुलाकात कर वास्तविक स्थिति जानने के लिए विदेश मंत्रालय ने पहल शुरू की है। यह पुष्टि हुई है कि उन सहित सात लोगों को हॉर्मुज स्टेट से कुछ दूर स्थित केसन द्वीप से ईरानी सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया। इनमें से तीन लोग अभी भी हिरासत में हैं।

अमृत का परिवार वर्तमान में उदयपुर के त्रियुगा नगरपालिका, गाईघाट में रह रहा है। दुबई की एक शिपिंग कंपनी में कार्यरत 30 वर्षीय अमृत को गिरफ्तार किए जाने का कारण और तिथि अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि उनके बारे में आवश्यक जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी ईरान में नेपाल के अवैतनिक महावाणिज्यदूत को दी गई है। विदेश मंत्रालय को प्राप्त दस्तावेजों में यह स्पष्ट नहीं है कि अमृत को कब गिरफ्तार किया गया। प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्री पौडेल ने कहा, यह पुष्टि हुई है कि अमृत को ईरानी सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया है, लेकिन उन्हें हिरासत में रखने के कारण स्पष्ट नहीं हैं और गिरफ्तारी की तिथि को लेकर भी भ्रम बना हुआ है। उन्होंने कहा, यह भी स्पष्ट नहीं है कि उन्हें हाल के युद्ध के दौरान गिरफ्तार किया गया या उससे पहले ही। इस बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश जारी है। कतर स्थित नेपाली दूतावास ईरान में अवैतनिक महावाणिज्यदूत के माध्यम से अमृत के बारे में जानकारी जुटाने और उनके परिवार से संपर्क करने का काम कर रहा है। उनके अनुसार, 25 दिसंबर को ओमान के समुद्र से जहाज रवाना हुआ था, जिसमें सात लोग सवार थे।

फोटोः हि.स.

हिरासत में लिए गए लोगों में से चार को उसी समय रिहा कर दिया गया था, जबकि अमृत और दो भारतीय नागरिक अभी भी हिरासत में हैं। अमृत और दो भारतीय नागरिकों को केसन द्वीप से हॉर्मुज क्षेत्र के अब्बास बंदरगाह स्थित जेल में स्थानांतरित किया गया है। उनकी रिहाई के लिए नियोक्ता कंपनी ब्लैक सी मरीन एलएलसी ने ईरान में वकील नियुक्त कर अदालत में याचिका दायर की है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) स्थित यह कंपनी कच्चे तेल के परिवहन का ठेका लेती रही है। वैदेशिक रोजगार विभाग के अनुसार, अमृत 19 जुलाई 2024 को सीमैन पद के लिए श्रम स्वीकृति लेकर यूएई गए थे। परिवार द्वारा कौंसुलर विभाग में दर्ज आवेदन के अनुसार, वे कंपनी के जहाज से दुबई से ईरान गए थे। अमृत की बहन पूजा ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्हें एक वॉइस मैसेज मिला, जिससे पता चला कि उनका भाई ईरान की जेल में है।

नोवुस लॉयल्टी ने आईपीओ निवेशकों को किया निराश

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर नोवुस लॉयल्टी लिमिटेड के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में फ्लैट एंट्री करने के बाद कमजोर प्रदर्शन कर अपने आईपीओ निवेशकों को निराश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 146 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग बिना किसी उतार चढ़ाव के 146 रुपये के स्तर पर ही हुई। लिस्टिंग के बाद बिकवाली का दबाव बन जाने के कारण थोड़ी ही देर में ये शेयर टूट 138.70 रुपये के लोअर सर्किट लेवल तक पहुंच गया। इस तरह पहले दिन के कारोबार में ही कंपनी के आईपीओ निवेशकों को 7.30 रुपये प्रति शेयर यानी पांच प्रतिशत का नुकसान हो गया। नोवुस लॉयल्टी लिमिटेड का 60.15 करोड़ रुपये का आईपीओ 17 से 20 मार्च के बीच

सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से एवरेज रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 1.55 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 1.38 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 1.17 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 1.82 गुना सब्सक्राइब हो सका था।

अमेरिका में गृह सुरक्षा विभाग की बजट फंडिंग और सीमा सुरक्षा पर खींचतान जारी

एजेंसी (हि.स.)
वाशिंगटन

अमेरिका में बजट फंडिंग और सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के बीच खींचतान जारी है। सीनेट डेमोक्रेट्स ने मंगलवार को कहा कि वे गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) को फिर से खोलने (बजट फंडिंग) के लिए किसी भी समझौते के हिस्से के तौर पर, आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) में सुधारों के लिए जोर देते रहेंगे। इससे फंडिंग की रुकावट का कोई हल निकालने की रिपब्लिकन पार्टी की कोशिशें और मुश्किल हो गई हैं। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सीनेट में अल्पमत दल के नेता और न्यूयॉर्क के सीनेटर चक शूमर ने यूएस कैपिटल में संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमें आईसीई पर लगाम लगानी होगी और हिंसा रोकनी होगी। हमें सुधारों की

फोटोः हि.स.

जरूरत है। इससे पहले सोमवार देर रात बातचीत में एक बड़ी सफलता मिलने के बाद सीनेट रिपब्लिकंस ने मंगलवार को डेमोक्रेट्स को एक औपचारिक प्रस्ताव भेजा। रिपब्लिकंस के एक समूह ने सोमवार शाम को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की और एक संभावित समझौते को लेकर आशावादी होकर कैपिटल लौटे। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या उनके पास कोई हल है तो अलबामा की सीनेटर केटी ब्रिट ने कहा, हां, हमारे पास है। लेकिन मंगलवार दोपहर को एक अहम बैठक के बाद डेमोक्रेट्स ने इस प्रस्ताव पर पानी फेर दिया और आईसीई में सुधारों की अपनी मांगों को दोहराया। जनवरी में मिनियापोलिस में फेडरल एजेंट्स की गोलीबारी की घटनाओं के बाद डेमोक्रेट्स ने सुधारों के बिना इस एजेंसी को फंड देने से इनकार कर दिया है। शूमर ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी के प्रस्ताव में इमिग्रेशन एजेंसी के लिए कोई सुधार शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत अभी भी जारी है और हम उन्हें अपना प्रस्ताव वापस भेजेंगे। शूमर ने कहा, और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि इसमें काफी अहम सुधार शामिल होंगे।

साउथ डकोटा के रिपब्लिकन सीनेट मेजोरिटी लीडर जॉन थून ने पत्रकारों को बताया कि रिपब्लिकन पार्टी का प्रस्ताव डीएचएस के बजट का 94 प्रतिशत हिस्सा फंड करेगा। आईसीई की डिपोर्टेशन विंग (एनफोर्समेंट एंड रिमूवल ऑपरेशंस) के लिए 5.5 बिलियन डॉलर सुरक्षित रखा जाएगा। थून ने मंगलवार को कहा कि कई सुधार आईसीई की फंडिंग पर निर्भर हैं।

वायदा बाजार में बढ़ी सोना और चांदी की कीमत, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी आई तेजी

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट का सामना कर रहे सोने और चांदी के भाव में आज अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर वायदा बाजार तक तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। घरेलू सराफा बाजार में भी सोना और चांदी दोनों चमकीली धातुओं ने आज जबरदस्त तेजी दिखाई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में सोना आज तीन प्रतिशत से अधिक और चांदी पांच प्रतिशत से अधिक उछल गया है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर अप्रैल की डिलीवरी वाला सोना 3.63 प्रतिशत उछल कर 1,43,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसी तरह मई में डिलीवरी वाली चांदी 5.52 प्रतिशत की छलांग लगा कर 2,36,300 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर

फोटोः हि.स.

रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो, सोना और चांदी के भाव में यहां भी तेजी का रुख बना हुआ है। सिंगापुर गोल्ड एक्सचेंज में आज हाजिर सोना 3.76 प्रतिशत की उछाल के साथ 4567.30 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह लंदन सिल्वर मार्केट में हाजिरी चांदी की कीमत आज 5.75 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 73.57 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंची हुई है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि पश्चिम एशिया में जंग थमने की उम्मीद बनने के कारण निवेशकों का रुझान एक बार फिर सोना और चांदी जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की ओर बढ़ने लगा है। पश्चिम एशिया में शांति होने की उम्मीद बनने के कारण डॉलर के प्रति भी आकर्षण कम हुआ है। इसका असर भी सोने और चांदी की कीमत पर सकारात्मक रूप से पड़ा है। कैपेक्स गोल्ड एंड इन्वेस्टमेंट्स के सीईओ राजीव दत्ता का कहना है कि पश्चिम एशिया में जैसे-जैसे लड़ाई थमने की उम्मीद बढ़ेगी, वैसे-वैसे सोना और चांदी दोनों चमकीली धातुओं की कीमत में भी तेजी आएगी। खासकर, चांदी की कीमत में तुलनात्मक तौर पर अधिक तेजी आ सकती है। पश्चिम एशिया में जारी जंग के कारण फिलहाल चांदी की औद्योगिक मांग काफी घट गई है, लेकिन जैसे ही पश्चिम एशिया में शांति स्थापित होगी या उस दिशा में सकारात्मक पहल होगी, वैसे ही चांदी की औद्योगिक मांग में भी बढ़ोतरी होगी। ऐसा होने पर चांदी की कीमत एक बार फिर रफ्तार पकड़ सकती है।

ईरान की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव, जोलघाद्र बने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव

तेहरान। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच मसूद पेजेशकियान ने देश की सुरक्षा संरचना में अहम बदलाव करते हुए पूर्व आईआरजीसी कमांडर मोहम्मद बगेर जोलघाद्र को सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एसएनएससी) का नया सचिव नियुक्त किया है। यह नियुक्ति अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई की मंजूरी के बाद की गई है। जोलघाद्र ने इस पद पर अली लारीजानी का स्थान लिया है, जिनकी हाल ही में एक हवाई हमले में मौत हो गई थी। राज्य मीडिया के अनुसार, जोलघाद्र ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) में ब्रिगेडियर जनरल रह चुके हैं और इससे पहले ह्यएक्सपीडिएंसी काउंसिलह्व के सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। उनका सैन्य और रणनीतिक अनुभव इस संवेदनशील पद के लिए अहम माना जा रहा है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव पद ईरान की सुरक्षा और विदेश नीति के निर्धारण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह परिषद सीधे सर्वोच्च नेता को रिपोर्ट करती है और देश के रणनीतिक फैसलों में केंद्रीय भूमिका निभाती है। मौजूदा क्षेत्रीय संघर्ष और अमेरिका-इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच यह नियुक्ति ईरान की सुरक्षा नीति को और सख्त और संगठित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से नीचे

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

पश्चिम एशिया में शांति होने की उम्मीद के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल (कच्चे तेल) की कीमत आज एक बार फिर 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से नीचे आ गई है। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10:15 बजे ब्रेंट क्रूड 99.17 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 88.51 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहे थे। इसके पहले ब्रेंट क्रूड पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार को 104.49 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं डब्ल्यूटीआई क्रूड ने 92.35 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर मंगलवार के कारोबार का अंत किया था। आज के कारोबार की शुरूआत में ब्रेंट क्रूड लगभग छह प्रतिशत की कमजोरी के साथ 99.83 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर खुला। ट्रेडिंग शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही ब्रेंट क्रूड की कीमत घट कर 97.18 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक आ गई। इस गिरावट के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत में इजाफा हुआ, जिससे थोड़ी देर के लिए ब्रेंट क्रूड उछल कर 100.03 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच गया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही इसकी कीमत एक बार फिर 100 डॉलर के स्तर से नीचे आ गई। सुबह 10:15 बजे तक का कारोबार होने के बाद ब्रेंट क्रूड 5.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 99.17 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा था। ब्रेंट क्रूड की तरह ही वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड में भी आज पांच प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। डब्ल्यूटीआई क्रूड ने आज 88.53 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से कारोबार की शुरूआत की।

संक्षिप्त-समाचार

चीन ने ईरान से जल्द शांति वार्ता शुरू करने की अपील की

बीजिंग/तेहरान। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच वांग यी ने अब्बास अराघची से फोन पर बातचीत कर जल्द से जल्द शांति वार्ता शुरू करने की अपील की है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा हालात में सभी पक्षों को हर अवसर का लाभ उठाकर बातचीत की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि संघर्ष का समाधान युद्ध नहीं, बल्कि संवाद और कूटनीति के जरिए ही संभव है। इस दौरान ईरान के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि उनका देश केवल अस्थायी युद्धविराम नहीं, बल्कि स्थायी समाधान चाहता है। उन्होंने चीन की ओर से दी जा रही मानवीय सहायता के लिए आभार भी जताया। यह बातचीत ईरान के अनुरोध पर हुई, जो क्षेत्र में बढ़ते संघर्ष के बीच कूटनीतिक प्रयासों को तेज करने का संकेत माना जा रहा है। चीन ईरान का एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार है और पहले भी शांति की अपील करता रहा है। हालांकि, चीन ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमलों का खुलकर समर्थन नहीं किया है, जिससे उसकी संतुलित कूटनीतिक नीति भी सामने आती है।

एलपीजी की किल्लत पर संसद परिसर में विपक्ष ने किया विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली। कांग्रेस समेत विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में रसोई गैस (एलपीजी) की किल्लत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने मकर द्वार पर खाली सिलेंडर की तस्वीरें लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। विरोध में शामिल नेताओं में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सांसद मनीष तिवारी, मणिकम टैगोर, राजद सांसद मीसा भारती और सपा सांसद धर्मेंद्र यादव समेत कई विपक्षी सांसद मौजूद रहे। सांसदों ने हाथों में एक बड़ा बैनर पकड़ रखा था, जिस पर लिखा था, 'खाली सिलेंडर, खाली वादे'। विपक्षी सांसदों ने मांग कि देशभर में एलपीजी की भारी किल्लत के बीच सरकार तुरंत कदम उठाकर गैस आपूर्ति सामान्य करे।

सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च हुआ विविड इलेक्ट्रोमेक का आईपीओ, 30 तक लगा सकते हैं बोली

नई दिल्ली। लो और मीडियम वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पैनल तथा ऑटोमेशन सिस्टम बनाने वाली कंपनी विविड इलेक्ट्रोमेक का 130.54 करोड़ रुपये का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 30 मार्च तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद दो अप्रैल को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि छह अप्रैल को अलॉटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर सात अप्रैल को एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं। इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 528 रुपये से लेकर 555 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 240 शेयर का है। विविड इलेक्ट्रोमेक के इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स को दो लॉट यानी 480 शेयरों के लिए बोली लगाना होगा, जिसके लिए उन्हें 2,66,400 रुपये का निवेश करना होगा। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 23.52 लाख शेयर जारी किए जा रहे हैं। इनमें 98 करोड़ रुपये के 17,65,200 नए शेयर और 4.68 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिये बेचे जा रहे हैं। इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए 47.42 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसके अलावा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए 33.27 प्रतिशत हिस्सा और नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए 14.27 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इसके अलावा कंपनी के मार्केट मेकर्स के लिए 5.05 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इस इश्यू के लिए हेम सिक्योरिटीज लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि एमयूजीएफ इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है। वहीं हेम फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मार्केट मेकर है।

पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद के कारण ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में शांति होने की उम्मीद के कारण ग्लोबल मार्केट से आज मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। इसके पहले पिछले सत्र के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग को लेकर जारी असमंजस की स्थिति की वजह से अमेरिकी बाजार कमजोरी के साथ बंद हुए थे। हालांकि डाउ जॉन्स फ्यूचर्स आज मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान मिला-जुला कारोबार होता रहा। वहीं एशियाई बाजार में आज चौतरफा तेजी का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध में सीजफायर को लेकर अमेरिका और ईरान की ओर से अलग-अलग बयान आने की वजह से पिछले सत्र के दौरान अमेरिकी बाजार में असमंजस की स्थिति बनी रही, जिसके कारण वॉल स्ट्रीट के सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। एस एंड पी 500 इंडेक्स 0.37 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 6,556.37 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 184.87 अंक 0.84 प्रतिशत की गिरावट के साथ 21,761.89 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। वहीं डाउ जॉन्स फ्यूचर्स आज फिलहाल 379.77 अंक यानी 0.82 प्रतिशत उछल कर 46,503.83 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है।

शुरूआती कारोबार में शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी का रुख, सेंसेक्स और निफ्टी उछले

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में शांति होने की उम्मीद के कारण घरेलू शेयर बाजार से आज मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। आज के कारोबार की शुरूआत भी तेजी के साथ हुई थी। बाजार खुलने के बाद खरीदारों ने लिवाली का जोर बना दिया, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की चाल में और तेजी आ गई। सुबह 10 बजे तक का कारोबार होने के बाद सेंसेक्स 1.56 प्रतिशत और निफ्टी 1.70 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे।आज सुबह 10 तक का कारोबार होने के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंट लिमिटेड, अदानी पोर्ट्स, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और अदानी एंटरप्राइज के शेयर 4.31 प्रतिशत से लेकर 3.12 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, कोल इंडिया और एचसीएल टेक्नोलॉजी के शेयर 2.21 प्रतिशत से लेकर 0.19 प्रतिशत की कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे।

जंगली हाथी के हमले में युवक की मौत, इलाके में दहशत

एजेंसी (हि.स.)
नवादा

नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के हरदिया पंचायत अंतर्गत सुअरलेटी गांव में बुधवार को जंगली हाथी के हमले में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है, जबकि मृतक के घर पर मातम पसरा हुआ है।

ग्रामीणों के अनुसार युवक रोज की तरह गांव के ही नोखी यादव के खटाल से दूध लेने गया था। दूध लेकर वह अपने घर लौट रहा था, तभी जंगल क्षेत्र में घूम रहे जंगली हाथी ने अचानक उस पर हमला कर दिया। हाथी ने युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। बताया जाता है कि मृतक अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। वह अपने पीछे पत्नी, तीन पुत्र और एक पुत्री को छोड़ गया है। उसकी असामयिक मौत से परिवार के सामने भरण-पोषण का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। घटना को

फोटोः हि.स.

लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र में हाथी के आने की जानकारी होने के बावजूद विभाग की ओर से न तो माइकिंग कर लोगों को सतर्क किया गया और न ही नियमित गश्ती की गई। ग्रामीणों का मानना है कि यदि समय रहते लोगों को चेतावनी दी जाती तो शायद यह दर्दनाक हादसा टल सकता था। वहीं जब ग्रामीण घटनास्थल की ओर गए तो देखा कि नोखी यादव की एक भैंस को भी हाथी ने मार दिया है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है और लोग शाम ढलते ही घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।

हौसलों की उड़ान | रोल्पा के सन्देश बुढामगर, जिनके लिए अक्षमता भी बनी शक्ति

हाथों ने छोड़ा साथ, तो पैरों से लिख रहे हैं अपना भविष्य

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

रोल्पा की ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों पर करीब डेढ़ घंटे पैदल चलकर 12 वर्षीय एक बालक रोज परीक्षा केंद्र पहुंचता है। फिर वह अपने पैरों से ही परीक्षा लिखकर वापस लौटता है। उनकी लिखावट में छिपा संघर्ष और मेहनत असाधारण है। ऐसा लगता है कि हर परीक्षा उनके लिए केवल शैक्षिक मूल्यांकन नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की भी परीक्षा है। सन्देश की यह प्रस्तुति देखने वाले लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं।

रोल्पा नगरपालिकाझ्र10 धवाङ, धाड्सी गांव के निवासी सन्देश बुढामगर इस समय अपने पैरों के सहारे अपना भविष्य लिख रहे हैं। नेपाल राष्ट्रीय आधारभूत विद्यालय की कक्षाझ्र5 के छात्र सन्देश परीक्षा देने के लिए दूसरे वॉर्ड में स्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालय पहुंचते हैं। वे जिले में चैत 8 गते से शुरू हुई पालिका-

फोटोः हि.स.

स्तरीय वार्षिक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के दौरान उनके लिए जमीन पर बैठने की व्यवस्था की जाती है और वे पैरों की उंगलियों से कलम पकड़कर लिखते हैं।

परिवार के लोग बताते हैं कि सन्देश के लिए जीवन की शुरूआत आसान नहीं थी। खाना खाने, कपड़े पहनने से लेकर दैनिक कामों में उनके हाथ साथ नहीं देते। जन्म से ही दोनों हाथ काम नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद सन्देश ने कभी खुद को कमजोर नहीं माना। उन्होंने अपनी कमजोरी को ही ताकत में बदलने का संकल्प लिया। नर्सरी कक्षा से ही उन्होंने पैरों से लिखने का अभ्यास शुरू कर दिया। आज वे कहते हैं, ह्लस्कूल जाना शुरू करने के बाद से ही मैंने पैरों से लिखने का अभ्यास किया। अब तो जितना भी लिखना पड़े, मैं आसानी से पैरों से लिख सकता हूं।

शिक्षक खिम बुढामगर के अनुसार सन्देश उत्तरपुस्तिका के सभी प्रश्नों के उत्तर साफ और समझने योग्य तरीके से पैरों से ही लिखते हैं। दुर्गम गांव में सड़क पहुंचने के बावजूद यातायात की सुविधा न होने के कारण वे रोज डेढ़ घंटे पैदल चलकर परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं। दुर्गम परिस्थितियों और गरीबी के कारण सन्देश के अभिभावक उनके हाथों के काम न करने का वास्तविक कारण पता नहीं लगा पाए हैं। उचित स्वास्थ्य जांच के अभाव में उनका इलाज भी नहीं हो सका है।

फिर भी, हाथों के काम न करने के बावजूद उनकी पढ़ने की लगन और आगे बढ़ने की इच्छाशक्ति सभी को एक संदेश देती है—अगर हिम्मत हो तो कोई भी बाधा सफलता के रास्ते को नहीं रोक सकती। सन्देश बुढामगर आज केवल रोल्पा ही नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प रखने वाले हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गए हैं।

क्रिकेट के इतिहास में पहली बार: अमेलिया केर ने रचा कीर्तिमान, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड ध्वस्त

दुनिया की पहली ऐसी खिलाड़ी: अमेलिया की लगातार 11 पारियों में 30+ रनों की ऐतिहासिक 'कंसिस्टेंसी'

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

न्यूजीलैंड की स्टार ऑलराउंडर अमेलिया केर ने साउथ अफ्रीका महिला टीम के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में शतकीय पारी खेलकर एक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने जो कारनामा किया है, उससे उन्होंने रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है।

अमेलिया केर अब दुनिया की पहली खिलाड़ी (पुरुष और महिला दोनों में) बन गई हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में लगातार 11 पारियों में 30 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं। दरअसल, चौथे टी20आई मैच के दौरान 31 रन बनाने के साथ ही उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में लगातार सबसे ज्यादा 30 प्लस स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और पांचवें टी20आई मैच में आज शतक जड़ने के बाद उन्होंने अपने

फोटोः हि.स.

इस रिकॉर्ड को सबसे अनोखा बना दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड श्रीलंका की चमारी अटापट्टू और रोमानिया की रेबेका ब्लेक के नाम था, जिन्होंने लगातार 9 बार ऐसा किया था। वहीं, में, टी20आई में मोहम्मद रिजवान, रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा के नाम ये रिकॉर्ड है, जिन्होंने लगातार 7 पारियों में 30+ स्कोर किया था। केर ने अब इन सबको काफी पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि अमेलिया केर ने पिछली 11 पारियों में 140 के स्ट्राइक रेट से 669 रन बनाए। उन्होंने गेंद से भी शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 12 विकेट लिए। हाल ही में केल महिला टी20आई में बतौर फुल आईसीसी मेंबर्स में सबसे तेज 1000 रन और 100 विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनीं।

सबसे ज्यादा लगातार 30 प्लस स्कोर बनाने वाले बैटर्स

अमेलिया केर- 11 बार
चमारी अटापट्टू-9 बार
रेबेका ब्लेक-9 बार
रोहित शर्मा- 7 बार
अभिषेक शर्मा- 7 बार

केन के दम पर न्यूजीलैंड ने 4-1 से जीती टी20 सीरीज

अमेलिया केर ने न्यूजीलैंड को पांचवें टी20आई मैच में 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 194 रन का स्कोर खड़ा करने में मदद की। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 102 रन ही बना सकी और न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम ने आखिरी टी20आई मैच 92 रन से अपने नाम किया और पांच मैचों की टी20 सीरीज को 4-1 से अपने नाम किया।

हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार में डबल नॉमिनेशन से आत्मविश्वास से भरे प्रिंस दीप

कहा- इससे मेरे मन के कई संदेह दूर हुए

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार 2025 में 'गोलकीपर ऑफ द ईयर' और 'अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर (अंडर-21 पुरुष)' के लिए नामित होने वाले प्रिंस दीप सिंह के लिए यह उपलब्धि सिर्फ एक सम्मान नहीं, बल्कि आत्मविश्वास बढ़ाने वाला बड़ा मोड़ है। प्रिंस ने हॉकी इंडिया के हवाले से कहा, मैं बहुत खुश और गर्व महसूस कर रहा हूं। आमतौर पर ऐसे अवॉर्ड के लिए समय लगता है, लेकिन मुझे जल्दी मौका मिला। इससे मेरे मन के कई संदेह दूर हुए और अब लगता है कि मैं सही दिशा में हूं।

युवा गोलकीपर ने अपने अब तक के सफर को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा दबाव में खुद को साबित करने की कोशिश की है। जूनियर वर्ल्ड कप में अहम मुकाबलों को याद करते हुए उन्होंने कहा, ऐसे मैचों में टीम का भरोसा बहुत मायने रखता है। जब साथियों ने मुझ पर विश्वास जताया, तो मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया और

फोटोः हि.स.

मैं टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन कर सका। प्रिंस ने बताया कि उनका करियर गोलकीपर के रूप में शुरू नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, मैं शुरूआत में डिफेंडर था, लेकिन फुटबॉल खेलते समय गोलकीपिंग करता था। वहीं मेरे कोच ने मेरी काबिलियत पहचानी और मुझे हॉकी में गोलकीपर बनने के लिए कहा। वहीं से मेरी असली यात्रा शुरू हुई। गोलकीपिंग को मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण बताते हुए प्रिंस ने कहा, इस पोजीशन पर हमेशा दबाव रहता है- चाहे दर्शकों का हो या मैच की स्थिति का। मैं मैच से एक दिन पहले ही मानसिक तैयारी शुरू कर देता हूं। मैदान पर लगातार संवाद बनाए रखना मुझे नियंत्रण में रखता है। सीनियर टीम में अभी तक पदार्पण नहीं करने के बावजूद दिग्गज गोलकीपर्स के साथ नामांकन पर उन्होंने कहा, भारत में गोलकीपर्स की मजबूत प्रतिस्पर्धा है। ऐसे खिलाड़ियों के बीच नाम आना मेरे लिए बहुत खास है और इससे मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अंत में उन्होंने अपने लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए कहा, मेरा सपना भारतीय सीनियर टीम का मुख्य गोलकीपर बनना और देश के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतना है। अगर मुझे यह अवॉर्ड मिलता है, तो मैं इसे अपने परिवार को समर्पित करूंगा, क्योंकि उनका समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है।

सीजन के अंत में लिवरपूल छोड़ेंगे मोहम्मद सालाह, भावुक संदेश में किया ऐलान

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

मोहम्मद सालाह ने मंगलवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वह मौजूदा सत्र के अंत में लिवरपूल फुटबॉल क्लब को छोड़ देंगे। सालाह ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में अपने विदाई संदेश की शुरूआत करते हुए इस फैसले की पुष्टि की। 33 वर्षीय सालाह ने कहा, दुर्भाग्य से यह दिन आ गया है। यह मेरी विदाई का पहला हिस्सा है। मैं इस सत्र के अंत में लिवरपूल छोड़ दूंगा।

उन्होंने क्लब, शहर और प्रशंसकों के साथ अपने गहरे जुड़ाव को याद करते हुए इसे अपने जीवन का अहम हिस्सा बताया। सालाह लिवरपूल के इतिहास में तीसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 435 मैचों में 255 गोल किए हैं और इस सूची में केवल इयान रश और रोजर हंट उनसे आगे हैं। 2017 में क्लब से जुड़ने के बाद उन्होंने दो प्रीमियर लीग खिताब, चैंपियंस लीग, एफए कप,

फोटोः हि.स.

सुपर कप, क्लब विश्व कप और लीग कप जैसे कई बड़े खिताब जीते। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह क्लब और यहां के लोग उनके जीवन का इतना बड़ा हिस्सा बन जाएंगे। उन्होंने अपने साथियों और प्रशंसकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके करियर के सबसे अच्छे और कठिन समय में मिले समर्थन को वह कभी नहीं भूलेंगे। मोहम्मद सालाह ने यह भी कहा कि लिवरपूल हमेशा उनके दिल में रहेगा और यह क्लब उनके लिए घर जैसा रहेगा।

उन्होंने भावुक शब्दों में कहा, यहां से जाना आसान नहीं है, लेकिन मैं हमेशा इस क्लब का हिस्सा रहूंगा।

न्यूजीलैंड क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में जेरेमी कोनी और हैडी टिफेन शामिल

एजेंसी (हि.स.)
वेलिंगटन

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपने हॉल ऑफ फेम में पूर्व ऑलराउंडर जेरेमी कोनी और हैडी टिफेन को शामिल किया है। यह पिछले साल घोषित फर्स्ट इलेवन के बाद पहली बार नए नाम जोड़े गए हैं। जेरेमी कोनी ने 1974 से 1987 के बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला और 1980 के दशक में न्यूजीलैंड टीम के स्वर्णिम दौर में अहम भूमिका निभाई। उनकी कप्तानी में टीम ने 1985 और 1986 में तीन ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत दर्ज की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को उनके घर और न्यूजीलैंड में तथा इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना शामिल था।

कोनी ने 52 टेस्ट मैचों में 2668 रन बनाए, जिसमें तीन शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं, जबकि गेंदबाजी में 27 विकेट लिए। वनडे क्रिकेट में उन्होंने 88 मैचों में 1874 रन और 54 विकेट हासिल किए। संन्यास के बाद वे सफल कमेंटेटर और प्रस्तुतकर्ता बने। वहीं, हैडी टिफेन को न्यूजीलैंड की

फोटोः हि.स.

सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटरों में गिना जाता है। उन्होंने 1999 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 19 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। टिफेन ने 117 वनडे मैचों में 2919 रन बनाए, जिसमें एक शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं, साथ ही 49 विकेट भी लिए। उन्होंने दो टेस्ट और नौ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले। कप्तान के रूप में उन्होंने टीम को 2009 विश्व कप के फाइनल तक पहुंचाया। संन्यास के बाद उन्होंने न्यूजीलैंड महिला टीम को कोचिंग भी दी। टिफेन ने इस सम्मान पर खुशी जताते हुए कहा कि यह उनके लिए बहुत बड़ा गौरव है और वह उन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ शामिल होकर सम्मानित महसूस कर रही हैं, जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया। गौरतलब है कि पिछले साल हॉल ऑफ फेम की शुरूआत के दौरान बर्ट सटक्लिफ, जॉन आर. रीड, जैकी लॉर्ड, ट्रिश मैककेल्वी, ग्लेन टर्नर, सर रिचर्ड हैडली, डेबी हॉकले, मार्टिन क्रो, एमिली ड्रम्म, डेनियल विटोरी और ब्रेंडन मैक्कुलम जैसे दिग्गजों को शामिल किया गया था। हॉल ऑफ फेम में शामिल होने के लिए खिलाड़ी का न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व करना और कम से कम पांच साल पहले संन्यास लेना जरूरी है। चयन खिलाड़ियों के प्रदर्शन, नेतृत्व क्षमता और उनके प्रभाव को ध्यान में रखकर किया जाता है। कोनी और टिफेन को औपचारिक रूप से न्यूजीलैंड क्रिकेट अवॉर्ड्स के दौरान सम्मानित किया जाएगा।

केकेआर ने आंद्रे रसेल के सम्मान में रिटायर की जर्सी नंबर 12

एजेंसी (हि.स.)
कोलकाता

आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को खास सम्मान देते हुए उनकी जर्सी नंबर 12 को रिटायर करने का ऐलान किया है। यह घोषणा टीम के प्री-सीजन इवेंट 'नाइट अनप्लग्ड 3.0' के दौरान की गई। रसेल, जिन्हें फ्रेंचाइजी ने 'इटरनल नाइट' का दर्जा दिया है, 2014 से 2025 तक केकेआर के लिए खेलते रहे और इस दौरान उन्होंने टीम को कई यादगार जीत दिलाईं। उन्होंने 140 आईपीएल मैचों में 2651 रन बनाए और 123 विकेट लिए। वह लीग के चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने 2000 से ज्यादा रन और 100 से अधिक विकेट का दोहरा आंकड़ा हासिल किया है। रसेल केकेआर की 2014 और 2024 की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभा चुके हैं। 2019 सीजन में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए

फोटोः हि.स.

उन्हें 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर' भी चुना गया था। इसके अलावा, 2021 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 5/15 का उनका प्रदर्शन केकेआर के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा है। केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर ने कहा कि रसेल का टीम के साथ लंबा और भावनात्मक रिश्ता रहा है और जर्सी नंबर 12 उनके साथ खास पहचान बन चुका है, इसलिए इसे रिटायर कर उन्हें सम्मान दिया गया। वहीं, रसेल ने इस मौके पर भावुक होते हुए कहा कि केकेआर के साथ उनका सफर बेहद खास रहा है और फ्रेंचाइजी ने इस यात्रा को यादगार बना दिया।

दर्पण करियर

सीएसयू नॉन-टीचिंग और लाइब्रेरियन भर्ती का प्रवेश पत्र जारी, 29 को परीक्षा

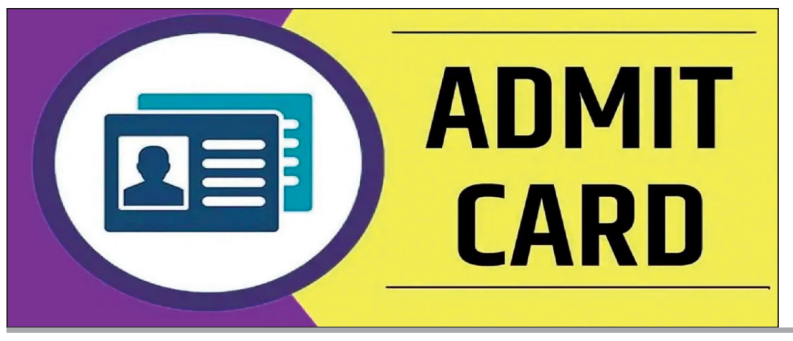

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (उरव), दिल्ली ने नॉन-टीचिंग स्टाफ और लाइब्रेरियन पदों के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 29 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी।

किन पदों के लिए जारी हुए एडमिट कार्ड

एडमिट कार्ड नॉन-टीचिंग स्टाफ और कॉलेज लाइब्रेरियन पदों के लिए जारी किए गए हैं। यह भर्ती देशभर के आदर्श संस्कृत महाविद्यालय (ASM) और आदर्श संस्कृत शोध संस्थान (ASSS) के लिए की जा रही है। लाइब्रेरियन पद के लिए अलग लिंक दिया गया है, जबकि अन्य पदों के लिए उम्मीदवार सामान्य पोर्टल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

भर्ती प्रक्रिया और पदों की जानकारी

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 43 नॉन-टीचिंग पद भरे जाएंगे। इसमें सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क (UDC), लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) और कॉलेज लाइब्रेरियन जैसे पद शामिल हैं। यह भर्ती भारत के नागरिकों के लिए आयोजित की जा रही है और इसकी योग्यता संबंधित नोटिफिकेशन में दी गई है।

जरूरी निर्देश

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड और पहचान पत्र साथ ले जाना जरूरी है। बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और सभी निर्देश ध्यान से पढ़ लें, ताकि परीक्षा के दिन किसी भी परेशानी से बचा जा सके।

आवेदन और परीक्षा की तारीख

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 जनवरी 2026 से शुरू होकर 27 फरवरी 2026 तक चली थी। अब उसी के तहत 29 मार्च 2026 को परीक्षा आयोजित की जाएगी।

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव (MCQ) और डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे।

दिल्ली हाईकोर्ट जेजेए भर्ती की उत्तर कुंजी जारी, 27 मार्च तक दर्ज करें आपत्ति

दिल्ली हाईकोर्ट ने जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट (JJA)/रेस्टोरर (ओपन) भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी रिस्पॉन्स शीट और आंसर की देख सकते हैं। इस कदम से परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। यह लिखित परीक्षा 22 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी, जिसमें देशभर से बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल हुए थे। आंसर की 24 मार्च 2026 को जारी की गई है, जिससे उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और संभावित अंक का अनुमान लगा सकते हैं।

आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया

अगर किसी उम्मीदवार को आंसर की में कोई त्रुटि नजर आती है, तो वह 24 मार्च से 27 मार्च 2026 तक (शाम 4 बजे तक) ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकता है। आपत्ति दर्ज करते समय उम्मीदवारों को उचित प्रमाण और संदर्भ देना होगा, ताकि बोर्ड उनकी जांच कर सके।

भर्ती प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तारीखें

इस भर्ती का नोटिफिकेशन 31 जनवरी 2026 को जारी किया गया था। आवेदन प्रक्रिया 4 फरवरी से शुरू होकर 23 फरवरी 2026 तक चली थी। इसके बाद 1 मार्च 2026 को उम्मीदवारों को अपने आवेदन में सुधार करने का मौका भी दिया गया था।

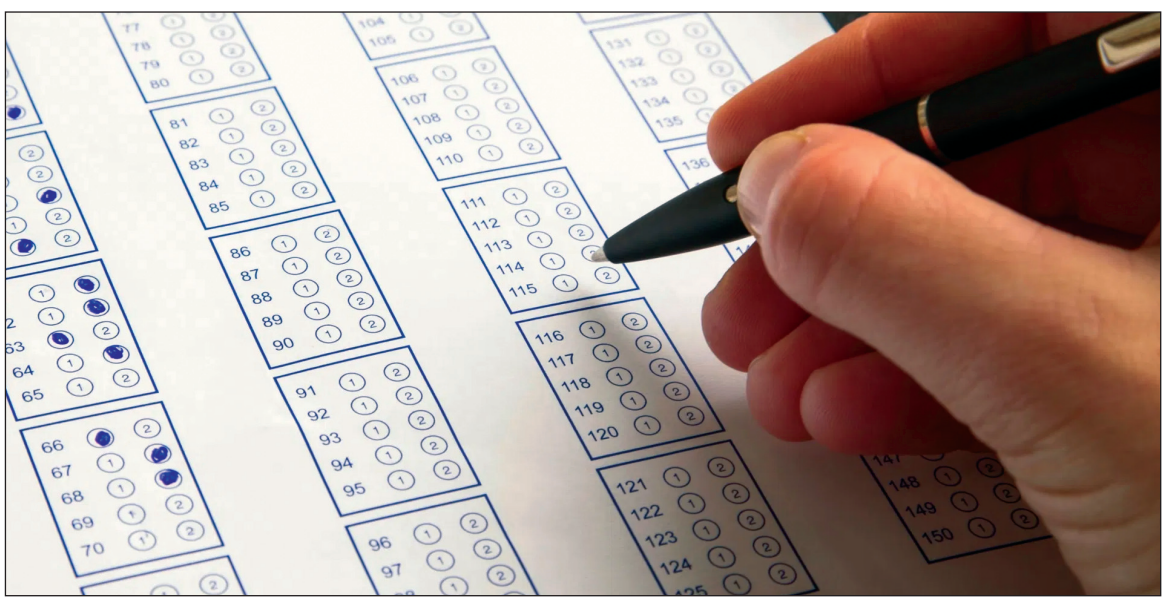

कुल पद और आरक्षण विवरण

इस भर्ती के तहत कुल 152 पद भरे जाएंगे। इनमें 62 पद सामान्य वर्ग के लिए, 12 ईडब्ल्यूएस, 44 ओबीसी, 20 एससी और 14 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं।

योग्यता और आयु सीमा

उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (ग्रेजुएट) होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार की टाइपिंग स्पीड कम से कम 35 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। आयु सीमा 18 से 32 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी।

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में कई चरण शामिल हैं। उम्मीदवारों को प्रीलिम्स, मेन्स, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा पास करनी होगी। हर चरण को पास करने के बाद ही उम्मीदवार अगले चरण में जा सकेगा।

आवेदन शुल्क और आगे की प्रक्रिया

आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 1500 रुपये रखा गया था, जबकि एससी, एसटी, महिला और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए यह 1300 रुपये था। आपत्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट सभी आपत्तियों की जांच करेगा और फाइनल आंसर की जारी करेगा। इसके बाद ही परिणाम घोषित किया जाएगा और आगे की चयन प्रक्रिया शुरू होगी।

केवीएस-एनवीएस भर्ती की टियर-2 परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, 27 से 31 मार्च तक एग्जाम

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने केवीएस और एनवीएस भर्ती की टियर-2 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने टियर-1 परीक्षा सफलतापूर्वक पास की है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, टियर-2 परीक्षा 27 मार्च से 31 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा हर दिन दो शिफ्ट, सुबह और दोपहर में आयोजित होगी। अलग-अलग दिनों में विभिन्न पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना होगा कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी अनिवार्य है। बिना हॉल टिकट के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए समय से पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना जरूरी है।

भर्ती में कुल पद और चयन प्रक्रिया

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 15,762 पदों को भरा जाएगा। इनमें केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के 9,921 पद और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) के 5,841 पद शामिल हैं। चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी। पहले टियर-1 परीक्षा, फिर टियर-2 परीक्षा आयोजित होगी। इसके बाद संबंधित पदों के लिए स्किल टेस्ट या इंटरव्यू लिया जाएगा। अंतिम चयन इन सभी चरणों के आधार पर किया जाएगा।

परीक्षा शेड्यूल (मुख्य पद)

27 मार्चः प्राइमरी टीचर, प्रशासनिक अधिकारी, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, वाइस प्रिंसिपल
28 मार्चः टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट इंजीनियर, फाइनेंस ऑफिसर
29 मार्चः प्राइमरी टीचर (स्पेशल एजुकेटर), प्रिंसिपल, एएसओ

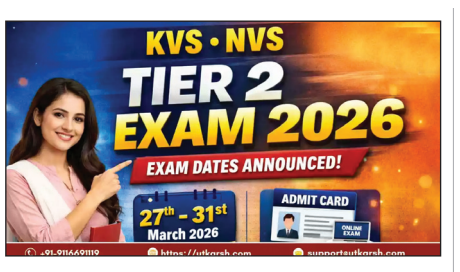

30 मार्चः लैब अटेंडेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर ट्रांसलेटर
31 मार्चः मल्टी टास्किंग स्टाफ उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें और परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें। साथ ही, एडमिट कार्ड की एक से अधिक कॉपी साथ रखना सुरक्षित रहता है।

परीक्षा पैटर्न और महत्वपूर्ण जानकारी

टियर-2 परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। यह परीक्षा शिक्षण और गैर-शिक्षण दोनों प्रकार के पदों के लिए आयोजित की जा रही है। उम्मीदवारों को अपने विषय के साथ-साथ सामान्य ज्ञान और अन्य संबंधित विषयों की भी अच्छी तैयारी करनी होगी।

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैंः आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या kvsangathan.nic.in पर जाएं। होमपेज पर भर्ती सेक्शन खोलें। 'Admit Card' लिंक पर क्लिक करें। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज करें। सबमिट करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।

प्रशासक ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को किया सम्मानित

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

चंडीगढ़ प्रशासन के खेल विभाग द्वारा आज खिलाड़ियों को सम्मानित करने हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सुश्री प्रेरणा पुरी, सचिव खेल, चंडीगढ़ प्रशासन ने गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया तथा शहर में खेल अवसंरचना के विकास और खेल गतिविधियों के प्रोत्साहन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया।

कार्यक्रम के दौरान माननीय प्रशासक ने 647 खिलाड़ियों को कुल 2.56 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की। अपने संबोधन में प्रशासक ने सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर शहर का नाम रोशन करने के लिए बधाई दी। उन्होंने खेल विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि विभाग युवा प्रतिभाओं को निखारने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने अभिभावकों को भी अपने बच्चों को खेलों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बधाई दी।

श्री कटारिया ने चंडीगढ़ के दिव्यांग छात्र खिलाड़ियों के प्रेरणादायक उदाहरणों का उल्लेख किया, जिन्होंने विभिन्न पैरा-ओलंपिक प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पहचान बनाई है। शहर की खेल क्षेत्र में बढ़ती पहचान पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने हाल ही में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मैराथन के सफल आयोजन का उल्लेख किया, जिससे चंडीगढ़ को वैश्विक पहचान मिली। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों का आयोजन किया जाएगा तथा खेल अवसंरचना और सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए हितधारकों से निरंतर सुझाव लिए जा रहे हैं।

प्रशासक ने कोचों की समर्पित भूमिका की भी सराहना की, जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि खेल छात्रों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, युवाओं को नशे से दूर रखते हैं तथा एक स्वस्थ और प्रगतिशील समाज के निर्माण में सहायक हैं।

उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए एक वर्ष में लगभग 28 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना देश में सबसे अधिक में से एक है। उन्होंने प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि खिलाड़ियों को सम्मानित और प्रोत्साहित करने के प्रयास भविष्य में भी जारी रहेंगे।

कार्यक्रम के दौरान छात्र खिलाड़ियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि नई चंडीगढ़ खेल नीति के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 48,000 रुपये किए जाने से उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए काफी प्रेरणा मिली है। खिलाड़ियों के अभिभावकों ने भी अपने बच्चों को सम्मानित होते देख प्रसन्नता और गर्व व्यक्त किया। इस अवसर पर श्री संजय टंडन, चेयरमैन, स्पोर्ट्स एडवाइजरी काउंसिल; श्री सौरभ अरोड़ा, निदेशक खेल; श्री नितीश सिंगला, निदेशक स्कूल शिक्षा; डॉ. महेंद्र सिंह, संयुक्त निदेशक खेल, यूटी सहित चंडीगढ़ प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने पंजाब के राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट

चंडीगढ़। श्री डेनिस अलीपोव, भारत में रूस के राजदूत, ने आज लोक भवन, पंजाब में पंजाब के राज्यपाल एवं यू.टी. चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया से शिष्टाचार भेंट की। यह बैठक सौहार्दपूर्ण एवं गर्मजोशी भरे वातावरण में संपन्न हुई, जिसमें आपसी हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। यह मुलाकात भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को दर्शाती है तथा दोनों पक्षों के बीच सहयोग, समझ और द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता को पुनः रेखांकित करती है।

कमेटी को सभी विभागों का सर्वे कर 10 अप्रैल तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिए निर्देश

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा की अध्यक्षता में दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत गठित जिलास्तरीय कमेटी की लघु सचिवालय के सभागार में बैठक हुई। डीसी ने 10 अप्रैल तक सभी विभागों का सर्वे कर कमेटी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में सभी सरकारी व निजी भवनों में दिव्यांग व्यक्ति व कर्मचारियों के लिए व्हीलचेयर व रैंप की सुविधा, दिवयांगों के लिए यूडीआईडी कार्ड बनवाने बारे, सभी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप, व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध करवाने बारे, सभी बैंकों में दिवयांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्हीलचेयर बारे विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने कमेटी को 10 अप्रैल तक पंचकूला के सभी सरकारी व गैर सरकारी, बैंकों, स्कूलों में यह सुविधाएं उपलब्ध हैं या नही, विजिट कर उपायुक्त कार्यालय में रिपोर्ट जमा करेगी। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि कमेटी दिव्यांगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य पुर्नवास और सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करे ताकि दिव्यांगों को अन्य नागरिकों की तरह अधिकार मिल सके। उन्होने सभी विभागों को दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्हीलचेयर व अन्य सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, अग्रणी बैंक प्रबंधक, पीडब्लयूडी के कार्यकारी अभियंता, आशा स्कूल चंडी मंदिर की प्रिंसीपल, मनोचिकित्सक नागरिक अस्पताल ने भाग लिया। इस अवसर पर डिप्टी डीईओ रमेश बत्रा, सदस्य एचईआरसी अंजू, एलडीएम गजल शर्मा, आशा स्कूल की प्रिंसीपल ममता रानी, मनोचिकित्सक डॉ लिजा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

पेक में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए जागरूकता सत्र का आयोजन

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), चंडीगढ़ ने छात्रों के भावनात्मक कल्याण और प्रभावी तनाव प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्पेशल काउंसलिंग सेल (एससीसी) के अंतर्गत एक मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सत्र का आयोजन किया। यह सत्र डीन स्टूडेंट अफेयर्स (डीएसए) डॉ. डी. आर. प्रजापति के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुश्री कोमिला पार्थी, प्रो. शोभना धीमन (रजिस्ट्रार, पेक), डॉ. सुलता भंडारी (हेड, एससीसी), डॉ. संदीप हरित, डॉ. गीता अरोड़ा, डॉ. तिलक ठाकुर तथा श्री नवीन कुमार उपस्थित रहे।

सत्र का संचालन मनोविज्ञान की एसोसिएट प्रोफेसर और अनुभवी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ सुश्री कोमिला पार्थी द्वारा किया गया। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए मानसिक स्वास्थ्य को एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में समझने की आवश्यकता पर बल दिया और भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य के बीच गहरे संबंध को रेखांकित किया।

उन्होंने कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, विजुअलाइजेशन तथा परिवार और मित्रों के सहयोग जैसे व्यावहारिक उपायों पर चर्चा की। साथ ही, ध्यान (मेडिटेशन) और भावनात्मक नियंत्रण के महत्व को भी उजागर किया। सत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू व्यक्तिगत सीमाएं निर्धारित करना और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए ह्लनाह्व कहना सीखना था।

डॉ. डी. आर. प्रजापति ने छात्रों को अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और आवश्यकता पड़ने पर सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। सत्र का समापन एक इंटरैक्टिव चर्चा के साथ हुआ, जिसमें छात्रों को तनाव प्रबंधन और समग्र कल्याण बनाए रखने के लिए उपयोगी सुझाव और व्यावहारिक उपकरण प्राप्त हुए।

पंजाब विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025झ्र2026 में जीसीई सेक्टर 20-डी चंडीगढ़ सी डिवीजन में पुरुष एवं महिला वर्ग में समग्र विजेता बना

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब विश्वविद्यालय का वार्षिक खेल पुरस्कार वितरण समारोह 2025झ्र2026 दिनांक 25 मार्च 2026 को विश्वविद्यालय के जिम्नेजियम हॉल में बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया।गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन (जीसीई), सेक्टर 20-डी, चंडीगढ़ ने सी डिवीजन श्रेणी में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। पुरुष वर्ग में कॉलेज ने शतरंज, खो-खो और एथलेटिक्स में विजेता ट्रॉफियां हासिल कीं, जो खिलाड़ियों की प्रतिभा, टीम भावना और समर्पण का प्रतीक है।

महिला वर्ग में जीसीई 20-डी ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को जारी रखते हुए बास्केटबॉल, बैडमिंटन और एथलेटिक्स में विजेता ट्रॉफियां जीतकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस शानदार उपलब्धि में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई जब जीसीई सेक्टर 20-डी चंडीगढ़ ने सी डिवीजन में पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में समग्र विजेता ट्रॉफी हासिल की – जो संस्थान की निरंतर उत्कृष्टता और खेलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन का प्रमाण है। यह उल्लेखनीय सफलता शारीरिक शिक्षा की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. नीलम पॉल के कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में संभव हुई, जिनकी प्रेरणा और निरंतर सहयोग ने खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। प्राचार्या डॉ. सपना नंदा ने विद्यार्थियों और स्टाफ की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उनके परिश्रम, अनुशासन और समर्पण की प्रशंसा की। उन्होंने पूरी टीम को संस्थान का नाम रोशन करने पर बधाई दी तथा भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखने के लिए प्रेरित किया।

उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कॉलेज को पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में 51,000-51,000 की नकद राशि से भी सम्मानित किया गया। यह अवसर जीसीई 20-डी के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं खेल समन्वयकों के लिए अत्यंत गर्व का क्षण रहा, जिनके सामूहिक प्रयासों ने संस्थान को यह गौरव दिलाया।

संक्षिप्त-समाचार

छात्रवृत्ति के 44.59 लाख की धोखाधड़ी मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ चालान पेश

चंडीगढ़/अंबाला। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला ने छात्रवृत्ति घोटाले के एक बड़े मामले में कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों के खिलाफ माननीय न्यायालय, कैथल में चालान पेश किया है। आरोपी धर्मबीर (बीएल सेंटर संचालक), राजेश कुमार और नवीन कुमार पर आरोप है कि उन्होंने सुनियोजित तरीके से फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से सरकारी छात्रवृत्ति राशि का गबन किया। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने शैक्षणिक सत्र 2013-14 और 2014-15 के दौरान 91 छात्र-छात्राओं के नाम पर फर्जी बैंक खाते खुलवाए और उन पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। इसके बाद पंजाब के शिक्षण संस्थानों में फर्जी दाखिले दशार्ते हुए छात्रवृत्ति के आवेदन तैयार किए गए। इन आवेदनों पर कालेजों की जाली मोहर, प्रिंसिपल के फर्जी हस्ताक्षर और फर्जी हाजिरी रजिस्टर लगाकर दस्तावेजों को वैध दिखाया गया। इन फर्जी दस्तावेजों को जिला कल्याण अधिकारी, कैथल के कार्यालय में जमा करवाकर छात्रवृत्ति राशि स्वीकृत करवाई गई। आरोपियों ने बायोमैट्रिक, चेक और अन्य माध्यमों से कुल 44,59,760 रुपये की राशि निकालकर अपने खातों में ट्रांसफर कर ली, जिससे हरियाणा सरकार और पात्र विद्यार्थियों को आर्थिक नुकसान पहुंचा। इस संबंध में 19 दिसंबर 2023 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान 29 दिसंबर 2025 को धर्मबीर, राजेश कुमार और नवीन कुमार को गिरफ्तार किया गया। इनमें से नवीन कुमार 6 फरवरी 2026 से जमानत पर है, जबकि धर्मबीर और राजेश कुमार फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। मामले में एक अन्य आरोपी, तत्कालीन बैंक अधिकारी हुकम चंद गुप्ता (सेवानिवृत) की गिरफ्तारी अभी लंबित है। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बताया कि मामले की गहन जांच के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ चालान न्यायालय में पेश कर दिया गया है तथा भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

पंचकूला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सर्वाधिक लिंगानुपात प्राप्त करने के लिए सम्मानित

पंचकूला। महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा पंचकूला जिले को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 में राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, पंचकूला डॉ. सविता नेहरा तथा जिला मिशन समन्वयक श्रीमती किरण भाटिया को महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी द्वारा सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि पंचकूला जिले के निरंतर प्रयासों और समर्पित कार्यशैली का परिणाम है। जिले में लिंगानुपात सुधारने हेतु डॉ. सविता नेहरा एवं उनकी टीम द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रभावी पहल की गई। ग्रासरूट स्तर पर उन गर्भवती महिलाओं से दूरभाष के माध्यम से नियमित संपर्क स्थापित किया गया, जिन महिलाओं के पास पहले से बेटियां हैं। दूरभाष पर संपर्क के दौरान उन महिलाओं को लिंग जांच करना तथा करवाना गैरकानूनी है, इस बारे भी जागरूक किया गया ताकि गर्भपात के मामलों को रोका जा सके। इस उपलब्धि के लिए सभी महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों, सुपरवाइजरों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास अत्यंत सराहनीय हैं। विभाग द्वारा भविष्य में भी इसी प्रकार पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य करते हुए जिले के लिंगानुपात को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखे जाएंगे।

पंचकूला नगर निगम ने निरीक्षण अभियान को निरंतर बनाए रखने हेतु साप्ताहिक शेड्यूल किया जारी

पंचकूला। नगर निगम पंचकूला द्वारा शहर में स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एक सुव्यवस्थित निरीक्षण अभियान निरंतर जारी है। इसी क्रम में आगामी सप्ताह के लिए विस्तृत निरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न वार्डों एवं सेक्टरों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही, पूर्व में कवर किए गए क्षेत्रों का औचक निरीक्षण भी निर्धारित किया गया है, ताकि फील्ड स्तर पर कार्यों की निरंतरता बनी रहे और संबंधित अधिकारी सतर्क रहें। जारी निरीक्षण आदेश के अनुसार 27 मार्च 2026 से 06 अप्रैल 2026 तक विभिन्न वार्डों जैसे वार्ड नंबर 3, 5, 8, 9 एवं 10 के अंतर्गत आने वाले सेक्टरों (सेक्टर-9, सेक्टर-10, सेक्टर-15, सेक्टर-19, सेक्टर-12, सेक्टर-123अ एवं सेक्टर-14) का निरीक्षण किया जाएगा। प्रत्येक दिन प्रातः 07:30 बजे से निरीक्षण प्रारंभ होगा तथा निर्धारित रूट के अनुसार विभिन्न बाजारों, आवासीय क्षेत्रों एवं गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की स्थिति, गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स का उन्मूलन,सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता, विकास कार्यों की प्रगति और बाजार क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा । नगर निगम पंचकूला द्वारा यह पहल शहर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित एवं नागरिकों के लिए बेहतर बनाने की दिशा में एक सतत प्रयास है।

नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय, पंजाब टेलीकॉम सर्किल, चंडीगढ़ ने सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थलों को बढ़ावा देने के लिए POSH कार्यशाला की मेजबानी की

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के अधीन चंडीगढ़ स्थित नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय, पंजाब टेलीकॉम सर्किल, ने अपने नियमित तथा संविदा कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम, 2013 पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्घाटन पंजाब सर्कल के नियंत्रक संचार लेखा श्री विजेंद्र नारायण टंडन द्वारा किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने समाज को आकार देने में कामकाजी और गैर-कामकाजी दोनों महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। श्री टंडन ने जोर दिया कि ढडरल्ल अधिनियम, 2013 का प्राथमिक उद्देश्य यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना, निषेध करना और संबोधित करना है ताकि महिलाओं के लिए सुरक्षित, सुरक्षित और सक्षम कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

श्री विजेंद्र नारायण टंडन ने आगे कहा कि ढडरल्ल अधिनियम, 2013 समानता और गरिमा के मौलिक अधिकारों को बनाए रखता है तथा नियोक्ताओं पर उत्पीड़न से मुक्त कार्यस्थलों को बनाए रखने की जिम्मेदारी डालता है। श्री टंडन ने यह भी रेखांकित किया कि आज के विकसित सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में, जहां महिलाएं समान जिम्मेदारियां साझा कर रही हैं, उनकी योगदानों को हर क्षेत्र में उचित रूप से मान्यता और सम्मान दिया जाना चाहिए। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और चंडीगढ़ की यूथ टेक्निकल ट्रेनिंग सोसाइटी की सदस्य डॉ. संगीता जुंड, कार्यशाला की अतिथि वक्ता थीं। उन्होंने अपनी सत्र की शुरूआत ढडरल्ल अधिनियम, 2013 के प्रमुख तत्वों–रोकथाम, निषेध, निवारण और संरक्षण–पर विस्तार से बताकर की। उन्होंने समझाया कि रोकथाम में जागरूकता और नीति कार्यान्वयन जैसे सक्रिय उपाय शामिल हैं; निषेध कार्यस्थल यौन उत्पीड़न के सभी रूपों पर कानूनी प्रतिबंध सुनिश्चित करता है; निवारण प्रभावी शिकायत निपटान के लिए आंतरिक समितियों की स्थापना पर केंद्रित है; और संरक्षण सभी महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण की गारंटी देता है, चाहे उनका रोजगार स्थिति कुछ भी हो। डॉ. जुंड ने इन पहलुओं को कवर करने वाली विस्तृत पावरपॉइंट प्रस्तुति दी, उसके बाद एक आकर्षक इंटरएक्टिव सत्र हुआ जहां प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से अपने प्रश्नों और दृष्टिकोण साझा किए। कार्यशाला का समापन सुश्री हरदीप कौर, लेखा अधिकारी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। सुश्री हरदीप कौर ने सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए पहल के लिए सी.सी.ए. पंजाब को धन्यवाद दिया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने परिवार सहित किए माता मनसा देवी के दर्शन

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने आज परिवार सहित चैत्र नवरात्र के सातवें दिन पंचकूला स्थित ऐतिहासिक माता मनसा देवी मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर महामाई का आशीर्वाद लिया। इसके उपरांत कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने मंदिर परिसर स्थित यज्ञशाला में मंत्रोच्चारण के बीच हवन-यज्ञ में भाग लिया और आहुति अर्पित की। इससे पूर्व उन्होंने मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि नवरात्र के पावन अवसर पर उन्हें माता मनसा देवी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि उन्होंने माता मनसा देवी के चरणों में नतमस्तक होकर देश और प्रदेश के लोगों के सुखमय एवं शांतिपूर्ण जीवन के लिए प्रार्थना की। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने मानव जीवन की सुरक्षा और विश्व में अमन-शांति बनाए रखने की भी कामना की।

कार्यक्रम **मोहाली में हुआ सेवा योजना सम्मेलन का सफल आयोजन**

पंजाब एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना सम्मेलन सम्पन्न

सिटी दर्पण संवाददाता
मोहाली

पंजाब एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के लिए आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) सम्मेलन का समापन चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में भव्य समापन समारोह के साथ सफलतापूर्वक हुआ। यह सम्मेलन युवाओं की भागीदारी और सामुदायिक सेवा को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इस सम्मेलन में पंजाब एवं चंडीगढ़ के राज्य राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार विजेता, स्वयंसेवक एवं विभिन्न अधिकारीगण शामिल हुए। यह आयोजन संवाद, सहयोग तथा श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान का एक सशक्त मंच बना, जिसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण को नई दिशा देना रहा।

समापन समारोह के मुख्य अतिथि प्रो. (डॉ.) आर. एस. बावा, सलाहकार, माननीय कुलाधिपति, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय सेवा योजना की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि यह युवाओं में जिम्मेदार नागरिकता के गुण विकसित करने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना युवाओं में निःस्वार्थ सेवा, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को सुदृढ़ करती है। उन्होंने संयुक्त राज्य स्तरीय सम्मेलन की पहल की सराहना करते हुए इसे पंजाब और चंडीगढ़ के बीच समन्वय एवं समग्र विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने युवाओं से ह्लविकसित भारत @ 2047ह्व के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया तथा कार्यक्रम अधिकारियों और समन्वयकों के प्रयासों की सराहना की।

इससे पूर्व स्वागत संबोधन में राष्ट्रीय सेवा योजना को युवा सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण के एक प्रभावी मंच के रूप में प्रस्तुत किया गया तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय एवं राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशालय के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया।

सम्मेलन के दौरान विभिन्न विशेषज्ञ सत्र, विचार-विमर्श, समूह चर्चाएँ एवं प्रस्तुतियाँ आयोजित की गईं, जिनके माध्यम से प्रतिभागियों ने अपनी उपलब्धियों की समीक्षा की, नवीन विचार साझा किए तथा जमीनी स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना को और मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए।

समापन अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय, चंडीगढ़ के क्षेत्रीय निदेशक श्री जय भगवान ने सम्मेलन के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह दो दिवसीय कार्यक्रम सक्रिय भागीदारी, सार्थक चर्चाओं एवं प्रभावी परिणामों से परिपूर्ण रहा, जो सभी प्रतिभागियों के लिए अत्यंत उपयोगी एवं प्रेरणादायक सिद्ध हुआ।

सम्मेलन के दौरान प्राप्त सुझावों एवं अनुशंसाओं को राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा, ताकि राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। सम्मेलन का समापन राष्ट्रीय सेवा योजना के मूल मंत्र ह्लमैं नहीं, आपह्व के संदेश के साथ हुआ, जिसने युवाओं में निःस्वार्थ सेवा और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को और मजबूत किया।